राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 7 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं, महत्त्वपूर्ण यह है।

-अज्ञात

भाई साथ-साथ

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने त्रिभाषा फार्मूले द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना का आरोप लगाया। हिन्दी को अनिवार्य बनाने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मार्च निकालने की तैयारी में थे। मगर सरकार के फैसला वापस करने के बाद विजय रैली निकाली जिसमें शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ने कहा कि अब हम एक-दूसरे का साथ देने के लिए आ गए हैं। मिल कर आपको (सरकार) बाहर कर देंगे। राज ने कहा, किसी भी झगड़े या विवाद से महाराष्ट्र बड़ा है। हम बीस साल बाद साथ आ रहे हैं। जो काम बाला साहेब नहीं कर सके, वह देवेंद्र फडनवीस ने कर दिखाया। आपसी अनबन के दो दशक लंबे अंतराल के बाद दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। भाजपा ने इसे खोए आधार को वापस पाने की हताश कोशिश और पारिवारिक मेल-मिलाप सरीखा ठहराया। उद्धव ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसी को धमकाएंगे नहीं, लेकिन उनको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमें धमकाते हैं। उन्होंने सभी मराठियों को साथ आने, मराठियों की पहचान को मिटना नहीं चाहिए जैसी बातें कीं जबकि राज ने मराठी को अपना एकमात्र एजेंडा बताया और कहा, हम महाराष्ट्र को बंटता हुआ नहीं देखना चाहते। असल सवाल है, दोनों ठाकरे पुराने सारे मतभेद मिटा कर साथ कैसे काम करते हैं। हालांकि, दोनों चचेरे भाइयों का आनन-फानन मंच साझा करना, शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले ठाकरे बंधुओं को इसका प्रतिफल तो जनता ही देगी क्योंकि मात्र भाषा के मुद्दे से देशवासियों को प्रभावित कर पाना आसान नहीं है। दुरगामी राजनीति करने के लिए ठाकरे बंधुओं को भाजपा गठबंधन को चुनौती देने के लिए बड़े मुद्दे तलाशने होंगे। मराठी मानुष के पक्षधर रहे बाल ठाकरे जिस हिन्दुत्व का बखान करते रहे थे, यह राग बिल्कुल उसके विपरीत जाता प्रतीत हो रहा है। मराठी बोलने को लेकर हाथापाई और अभद्रता के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर जनता में नाराजगी है। मुंबई में उत्तर भारतीयों ही नहीं, दक्षिण भारतीयों के वोट बैंक को कई दशकों से तवज्जो दी जा रही है। हालांकि सत्ता के लिए गठजोड़ करना आम है परंतु ठाकरे परिवार की राजनीति हुलमुलाती नजर आ रही है। तमाम कटुटरता के बाजूद राज को पिछले चुनावों में मिली करारी मात को भी नहीं भूलना चाहिए। भाषा, वेशभूषा या रहन-सहन के आधार पर देश को बांटा जाना उचित नहीं कहा जा सकता।

ये सूरत बदलनी चाहिए

सहिष्णु स्वीकारोक्ति, सच्चाई का सामना या सरकार को आईना दिखाना कहें, या कुछ और लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जो कहा उसे सरकार के रुख के विपरीत तो कहा ही जा सकता है। उन्होंने जो कहा उसका साफ-साफ अभिप्राय: यही है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र के हवाले से कुछ समय पहले कहा गया था कि देश में 33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। संघ और अपने गढ़ नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि धन का विकेंद्रीकरण जरूरी है। उन्होंने कृषि, विनिर्माण, कराधान और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित कई मुद्दों पर बात की। उनका इशारा अमीरों के धन पर शिकंजा ढीला करने की तरफ था। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित होना चाहिए कि रोजगार पैदा हों और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो। उदार आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की प्रशंसा की। उनके अनुसार ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार चल रहा है, जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में क्षेत्रीय योगदान में असंतुलन से चिंतित दिखाई दिए। विनिर्माण क्षेत्र 22-24 फीसद, सेवा क्षेत्र 52-54 फीसद योगदान देता है, जबकि कृषि, ग्रामीण आबादी के 65-70 फीसद हिस्से को शामिल करने के बावजूद केवल 12 फीसद योगदान देती है। कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में और अधिक होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) की पीठ ठोकते हुए केंद्रीय मंत्री ने उनमें अन्य क्षेत्रों में भी दखल बढ़ाने को कहा। वे अर्थव्यवस्था के वृद्धि इंजन हो सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी जमा करने तक ही सीमित न रहें। गडकरी ने अपने मंत्रालय के काम का हवाला देते हुए कहा कि सड़क विकास के लिए धन की कमी नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, बल्कि मेरे पास काम की कमी है। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जनता से पैसा वसूल कर खजाना भरना ही योग्यता नहीं है। गरीबों की बढ़ती संख्या और चंद लोगों के अमीर होते जाने की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है।

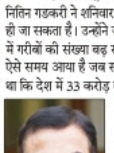

वन्यजीव संकट/सोनम लववंशी

पारिस्थितिकी की टूटती कड़ी

हमारे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला 'वन महोत्सव' केवल औपचारिकता बन कर न रह जाए, इसके लिए अब गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। इस उत्सव का मूल उद्देश्य वनों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। क्या एक सप्ताह की सक्रियता हमारे घटते वनों की पीड़ा को शांत कर सकती है? भारत एक समय हराभरा देश था। आज वे हरियाली लगातार सिकुड़ती जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र लगभग 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 24.62 प्रतिशत है।

यह आंकड़ा सुनने में बड़ा प्रतीत होता है। जब यह ज्ञात होता है कि इसमें से 12 फीसद से अधिक क्षेत्र केवल स्क्रब, झाड़ियां या क्षतिग्रस्त वन भूमि है, तब स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है। वैश्विक औसत के मुकाबले भारत वन आच्छादन में अब भी पीछे है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसी देश का कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अब भी अधूरा है। बढ़ती वन कटाई और अवैध शिकार का एक दर्दनाक प्रमाण देश में बाघों की लगातार हो रही मौतें हैं। वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में ही 107 बाघ अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 20 मासूम शावक भी शामिल हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक है और बीते पांच वर्षों में सबसे भयावह आंकड़ा है। वैसे भी जब एक पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है, तो उसकी कड़ी में जुड़े सभी अंग प्रभावित होते हैं जिनमें हम भी शामिल हैं। वनों के संरक्षण के लिए सरकारें पौधरोपण अभियान चलाती है। प्रश्न यह है कि क्या यह पर्याप्त है? वरसात के मौसम में लगाए गए पौधे जीवित भी रह पाएं, इसके लिए देखरेख और स्थानीय लोगों की सहभागिता आवश्यक है। 'चिपको आंदोलन' की तरह आज फिर से जनआंदोलन की जरूरत है। सोशल मीडिया पर पर्यावरण बचाने की बातें करने से आगे बढ़ना होगा। स्थानीय स्तर पर पौधे लगाने, संरक्षित करने और जंगलों को बचाने के ठोस प्रयास करने होंगे। वनों को बचाने के लिए नीति निर्धारण में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल शहरी क्षेत्रों में पौधरोपण कर लेने से पर्यावरण नहीं बचेगा। वन महोत्सव का यह सप्ताह महज एक उत्सव नहीं है। यह एक चेतावनी है। समय रहते नहीं चेते तो सांस लेने के लिए हवा भी बाजार में बिकेगी।

भाषा विवाद के मायने

महाराष्ट्र

विनीत नारायण

मलाही भाषा येत नाही। भाषा संवाद के लिए होती है, झगड़े उपद्रव के लिए नहीं।झगड़े उपद्रव के लिए लठ्ठबाजी, गोलीबारी होती है। गले लगा तो लो! बिना भाषा के भी संवाद हो जाता है। राष्ट्र में महाराष्ट्र का होना गौरव और गरिमा की बात है। महाराष्ट्र की उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति है। इसे क्षुद्र स्तर पर न ले आने के लिए हम सजग सावधान रहें तो इसकी सभ्यता-संस्कृति पूरे विश्व में जगमगाती रहेगी। मराठी-गुजराती-हिन्दी-अंग्रेजी की यहां सब नदियां एक ही महासागर से जुडी हैं। इसलिए यहां संकीर्णता नहीं, उदारता ही प्रवाहमान होती है। सभ्यता-संस्कृति का दीप-स्तंभ बनती है। यह कहना है स्वामी चैतन्य कीर्ति का।

इस विषय में ओशो क्या कहते हैं : 'एक मित्र ने पूछा है कि क्या भारत में कोई राष्ट्र भाषा होनी चाहिए? यदि हां, तो कौन सी? राष्ट्र भाषा का सवाल ही भारत में बुनियादी रूप से गलत है। भारत में इतनी भाषाएं हैं कि राष्ट्र भाषा सिर्फ लादी जा सकती है, और जिन भाषाओं पर लादी जाएगी उनके साथ अन्याय होगा। भारत में राष्ट्र भाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत में बहुत-सी राष्ट्रभाषाएं ही होंगी और आज कोई कठिनाई भी नहीं है कि राष्ट्र भाषा जरूरी हो। रूस बिना राष्ट्र भाषा के काम चलाता है, तो हम क्यों नहीं चला सकते? आज तो यांत्रिक व्यवस्था हो सकती है संसद में, बहुत थोड़े खर्च से, जिसके द्वारा एक भाषा सभी भाषाओं में अनुवादित हो जाए, लेकिन राष्ट्र भाषा का मोह बहुत महंगा पड़ रहा है। भारत की प्रत्येक भाषा राष्ट्र भाषा होने में समर्थ है। इसलिए कोई भी भाषा अपना अधिकार छोड़ने को राजी नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि हमने जबरदस्ती किसी भाषा को राष्ट्र भाषा बना कर थोपने की कोशिश की तो देश खंड-खंड हो जाएगा। आज देश के बीच विभाजन के जो बुनियादी कारण हैं, उनमें भाषा एक है। राष्ट्र भाषा बनाने का खयाल ही राष्ट्र को खंड-खंड में तोड़ने का कारण बनेगा। अगर राष्ट्र को बचाना हो तो राष्ट्र भाषा से बचना पड़ेगा और अगर राष्ट्र को मिटाना हो तो राष्ट्र भाषा की बात आगे भी जारी रखी जा सकती है। मेरी दृष्टि में भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, सब राष्ट्र भाषाएं हैं, उनको समान आदर उपलब्ध होना चाहिए। किसी एक भाषा का साम्राज्य दूसरी भाषा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वह भाषा चाहे हिन्दी हो और चाहे कोई और हो। कोई कारण नहीं है कि तमिल, तेलुगू, बंगाली या गुजराती को हिन्दी दबाए। लेकिन गांधी जी के कारण जो कुछ बीमारियां इस देश में छूटीं, उनमें एक बीमारी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का वहम देने की भी है। हिन्दी को यह अहंकार गांधी जी दे गए कि वह राष्ट्र भाषा है तो हिन्दी प्रांत उस अहंकार से परेशान हैं, और वे अपनी भाषा को पूरे देश पर थोपने की कोशिश में लगे हुए हैं। हिन्दी का साम्राज्य भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो किसी भाषा का नहीं किया जा सकता। सिर्फ संसद में हमें यांत्रिक व्यवस्था करनी चाहिए कि सारी भाषाएं अनुवादित हो सकें। और वैसे भी संसद कोई काम तो कोई करती नहीं है कि कोई अड़चन हो जाएगी। सालों तक एक-एक बात पर चर्चा चलती है, थोड़ी देर और चल लेगी तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। संसद कुछ करती ही तो भी विचार होता कि कहीं कार्य में बाधा न पड़ जाए। कार्य में कोई बाधा पड़ने वाली नहीं मालूम होती। फिर मेरी दृष्टि यह भी है कि यदि हम राष्ट्र भाषा को थोपने का उपाय न करें तो शायद बीस-पच्चीस वर्षों में कोई एक भाषा विकसित हो और धीरे-धीरे राष्ट्र के प्राणों को घेर ले। वह भाषा हिन्दी नहीं होगी, वह भाषा हिन्दुस्तानी होगी। उसमें तमिल के शब्द भी होंगे, तेलुगू के भी, अंग्रेजी के भी, गुजराती के भी, मराठी के भी। वह एक मिश्रित नई भाषा होगी जो धीरे-धीरे भारत के जीवन में से विकसित हो जाएगी। लेकिन, अगर कोई शुद्धतावादी चाहता हो कि शुद्ध हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना है, तो वह सब पागलपन की बात है। इससे कुछ हित नहीं हो सकता।' यह तो थी ओशो की सीख।

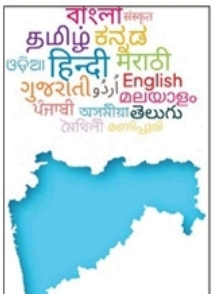

गांधी जी के कारण जो कुछ बीमारियां इस देश में छूटीं, उनमें एक बीमारी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का वहम देने की भी है। हिन्दी को यह अहंकार गांधी जी दे गए कि वह राष्ट्र भाषा है तो हिन्दी प्रांत उस अहंकार से परेशान हैं, और वे अपनी भाषा को पूरे देश पर थोपने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरी दृष्टि अगर कोई शुद्धतावादी चाहता हो कि शुद्ध हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना है, तो यह सब पागलपन की बात है।

महाराष्ट्र, एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और मराठी भाषा के लिए जाना जाता है, आज भाषा विवाद के कारण चर्चा में है। मराठी, जो इस राज्य की आत्मा है, न केवल एक भाषा है, बल्कि महाराष्ट्र की पहचान, इतिहास और गौरव का प्रतीक भी है। हाल के वर्षों में मराठी भाषा के उपयोग और सम्मान को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जो सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर तनाव का कारण बन रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। विशेष रूप से मुंबई जैसे महानगरों में, जहां विविधता अपनी चरम सीमा पर है, मराठी भाषा को कई बार उपेक्षित महसूस किया जाता है। गैर-मराठी भाषी समुदायों की उपस्थिति और वैश्वीकरण के प्रभाव ने मराठी के उपयोग को कुछ हद तक सीमित किया है। यह स्थिति स्थानीय लोगों में असंतोष को जन्म देती है, जो अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, साहित्य और परंपराओं की वाहक भी है। मराठी साहित्य में संत ज्ञानेश्वर से लेकर आधुनिक लेखकों तक का योगदान शामिल है, जो विश्व स्तर पर अपनी गहराई के लिए जाना जाता है। फिर भी, सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर मराठी के उपयोग में कमी देखी जा रही है।

यह स्थिति मराठी भाषी समुदाय के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने मराठी को अनिवार्य करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे स्कूलों में मराठी पढ़ाई को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यों में इसका उपयोग सुनिश्चित करना। लेकिन इन प्रयासों को और प्रभावी करने की आवश्यकता है। साथ ही, मराठी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। गैर-मराठी भाषी लोगों को भी मराठी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सामाजिक एकता मजबूत हो। मराठी भाषा या देश की अन्य भाषा का संरक्षण केवल एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और सहयोग जरूरी है। मराठी और अन्य भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा ताकि सभी भाषाएं अपनी गरिमा और गौरव के साथ फलती-फूलती रहें।

(लेख में विचार निजी हैं)

अभियान | श्रीराम शर्मा आचार्य

एक घर के मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी-सी दुकान थी उससे जो आय होती थी, उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूंकि परिवार में कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वह लोगों के सामने डींग हांका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, 'दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है।' सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, 'मैं दिन भर काम कर जो पैसे लाता हूं, उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे।' संत बोले, 'यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है।' इस पर मुखिया ने कहा, 'आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए।' संत ने कहा, 'ठीक है। तुम बिना किसी को बताए घर से एक महीने के लिए गायब हो जाओ।' उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक-संतप्त रहे। गांव वाले आखिरकार, उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहां नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिल कर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने को तैयार हो गया। एक महीने बाद मुखिया छिपता-छिपाता रात के वक्त अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझ कर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताईं तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, 'हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब हम पहले से ज्यादा सुखी हैं।' उस व्यक्ति का सारा अभिमान और वहम चूर-चूर हो गया। संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता!! यहां सभी के बिना भी काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। जगत को चलाने की हाम भरने वाले बड़े-बड़े सम्राट, मिट्टी हो गए, जगत उनके बिना भी चला है। इसलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का, अपने ज्ञान का अभिमान करना व्यर्थ है। इस प्रकार के भ्रम से निकलना ही श्रेयस्कर है।

मानसून में त्वचा की हर परेशानी का हल शहद

- **अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, शहद गाढ़ा, मीठा तरल होता है, जो मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज नाम की प्राकृतिक शर्करा से बना होता है। इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स और कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं**
- **शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण इसे मानसून में स्किनकेयर के लिए परफेक्ट बनाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, शहद का काम इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह किस पौधे या फूल से प्राप्त हुआ है**

(मीडिया इनपुट्स)

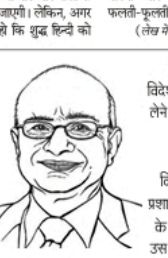

वताड की बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लेने या सीमा-पार आतंकवाद की बात करने की बजाय 'आतंकवाद' का जिक्र भर किया। वास्तविकता यह है ट्रंप प्रशासन पीड़ित और साजिशकर्ता के बीच ज्यादा भेद नहीं करता। उस पर ट्रंप तो यह भी दावा कर चुके हैं, 'आई लव पाकिस्तान'।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

रीडर्स मेल

बरसात में बचके

बरसात के मौसम में कई बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। पीने के पानी में लापरवाही से डायरिया और अन्य बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए पानी उबाल कर पीना चाहिए। बरसात के मौसम में साफ-सफाई की बहुत जरूरत होती है। आपने आसपास सफाई रख करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों को भी सफाई के प्रति जागरूक करना चाहिए। शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के लिए साफ पीने वाले पानी का उचित प्रबंध करें। जो लोग खाने-पीने की चीजें बेचते हैं, उन्हें चाहिए कि वो साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। न कि अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा दें। सरकार को चाहिए कि जो खाने-पीने की चीजें बेचते हैं, उनकी चीजों की समय-समय पर जांच करे। अगर बरसात में सावधानी बरती जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बरसात में कई जहरीले कीड़े-मकौड़े, सांप इत्यादि बहुत मात्रा में विचरने लगते हैं। कई बार ये कई लोगों को शिकार बना कर उनकी जान ले लेते हैं। इनसे बचने के लिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, और उसके इलाज में थोड़ी भी देरी हो जाती है, तो वो जान पर भी भारी पड़ सकती है। इस मौसम में खाने-पीने की चीजों को ढंक कर रखना चाहिए। छोटी-छोटी सावधानियां कई बार जान भी बचा देती हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सराहनीय फैसला

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। अनुसूचित जाति को 15 फीसद एवं अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसद संविधान सम्मत आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रधान न्यायाधीश के आदेशानुसार जारी परिपत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक पर यह नियम लागू होगा। देखा जाए तो यह ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जुलाई, 1997 में दिए गए एक आदेश को लगभग 29 वर्ष बाद अब जाकर लागू किया गया है। आजादी के 78 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागतयोग्य है, क्योंकि इस प्रावधान के तहत अब अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा जो संविधान की मूल भावना है। सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपेक्षा की जाती है कि कॉलेजियम के माध्यम से उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी तत्काल एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए और इस वर्गों को देश के सभी उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट में उचित प्रतिनिधित्व जल्द से जल्द प्रदान किया जाए।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

तत्काल कदम उठाएं

प्रलोभन देख कर धर्मांतरण कराने के मामले हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार का धर्मांतरण किसी सिद्धांत से प्रेरित नहीं होता है। मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का लाभ फायदा उठा कर अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य किसी धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ाना होता है। शक्ति प्रदर्शन के अवसरों पर यह भीड़ काम आती है। सरकार को इस प्रकार के धर्मांतरण को रोकने के लिए तत्काल समुचित कदम उठाना चाहिए।

ललित महालकरी, इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

वन्यजीव संकट/सुरेश भाई

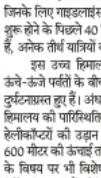

उड़ानों को नियंत्रित करना होगा

हिमालयी क्षेत्र | सुरेश भाई

मनुष्य अपनी यात्रा को आरामदायक और जल्दी पूरा करने के लिए हेली सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ी तेजी से कर रहा है। आजकल मध्य हिमालय की देवभूमि उत्तराखंड स्थित चारधाम के दर्शन करने पहुंच रहे यात्री भी हेली सेवाओं के उपयोग करने में पीछे नहीं हैं। अनेक कंपनियों के हेलीकॉप्टर यहां बड़ी संख्या में उड़ान भर रहे हैं, जिनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बावजूद इसके यात्रा शुरू होने के पिछले 40 दिनों में पांच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए हैं, अनेक तीर्थ यात्रियों की जान गई है।

इस उच्च हिमालयी क्षेत्र की संकरी घाटियों और ऊंचे-ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजर रहे हेलीकॉप्टर्स पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अंधाधुंध उड़ानें और उनकी तेज आवाज हिमालय की पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। हेलीकॉप्टरों की उड़ान के लिए मंदाकिनी नदी के तट से 600 मीटर की ऊंचाई तक का मानक है। यात्रियों की सुरक्षा के विषय पर भी विशेष सावधानी बरतने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से उच्च हिमालयी क्षेत्रों की जैव-विविधता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा भी इस हिमालय क्षेत्र में उड़ानों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें केदारनाथ की हेली सेवाओं की गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। यहां एक बार में दो हेलीकॉप्टर ही आना-जाना कर सकते हैं। सायं के समय की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद यहां पर स्थित दुर्लभ वन्य जीव हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, भरड़, भालू, मोनाल समेत अनेक वन्य जीवों व पक्षियों के झुंड के बीच नीची उड़ान के कारण भगदड़ मच जाती है, जिस कारण असुरक्षित दिशा में भागने से इन वेजुबान जानवरों की चट्टानों से गिर कर मौत हो जाती है। वन विभाग भी इस बाबत चेतावनी देता रहता है, लेकिन जीव-जंतुओं का जान गंवाना जारी है।

चिंताजनक है कि हजारों हैक्टेयर में फैले केदारनाथ अभयारण्य, गंगोत्री वन्य जीव पार्क के जीव-जंतु सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हेलीकॉप्टरों की नीची उड़ान के कारण बन्यजीवों के सहवास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण उनकी संख्या भी घट सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नीची

उड़ान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर भी बढ़ सकती है जबकि पर्यटकों और सैलानियों के सैर-सपाटे लिए ओम पर्वत जैसे ग्लेशियरों के ऊपर भी उड़ानें भरी जा रही हैं। अनियंत्रित पर्यटकों की आवाजाही इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बहुत समय से अनुभव किया जा रहा है कि चारधाम के यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए जब-जब राज्य सरकार और पर्यावरणविद् पहल करते हैं, तो स्थानीय स्तर पर पर्यटन से आया प्राप्त करने वाले संस्थान विरोध पर उतारू हो जाते हैं। मध्य हिमालय में पहुंच रहे पर्यटक कम पैसे, कम समय में आरामदायक दर्शन करने के लिए हेली सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में में सावधानी के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का इस्तेमाल नहीं होता है तो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा। लापरवाही और मानकों की अनदेखी से दुर्घटनाएं हो रही हैं। अंधाधुंध हेली सेवाओं के ऊपर विशेष जांच और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जिसमें तकनीक आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौसम विभाग की अधिकतर सूचनाएं सही साबित हो रही हैं। इसको भी ध्यान में रख कर उड़ानों पर नियंत्रण हो।

चारधाम में मई और जून के महीने में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं ने बहुत चिंताजनक स्थिति खड़ी की है जिसमें सबसे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोग मारे गए थे जिसके चार दिन बाद बद्रीनाथ से लौट रहा एक अन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 17 मई को एम्स की हेली एंबुलेंस किसी यात्री को लिफ्ट करने केदारनाथ जा रही थी, लेकिन क्रैश हो गई। 8 जून को केदारनाथ जाने वाला एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा है एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें सात लोगों की जान चली गई। दूसरी ओर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने चारधाम के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण लगभग पूरा कर दिया है, और इसमें दो बड़ी गाड़ियों के लिए आने-जाने की सुविधा है। जितने अधिक से अधिक लोग बस, टैक्सी और जमीन पर चलने वाले वाहनों से यात्रा करेंगे उससे स्थानीय होटल और ढाबों को भी रोजगार मिलेगा। पर्यटकों, यात्रियों, सैलानियों को भी यहां की प्रकृति का नजारा देखने को मिलेगा। बाहर से आने वाले लोगों की मुलाकात स्थानीय लोगों से होगी, वे यहां की संस्कृति और प्रकृति के साथ अनुकूल व्यवहार भी करेंगे। उत्तराखंड हिमालय की संवेदनशील स्थिति और यहां के पर्यावरण से प्लास्टिक उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी को बचाने के साथ ही हिमालय के इकोसिस्टम को भी बचा कर रखना होगा।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया गारा कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशन एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां माल, नवमंजिल हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 319
नए.एन.आई. से 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कमुनी वालों के लिए उत्तरदायी

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 120

समझौते की प्रतीक्षा

अमेरिका द्वारा व्यापार शुल्क वृद्धि पर स्थगन की 9 जुलाई की समय-सीमा करीब है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत और अमेरिका तय समय में साझा फायदे वाले समझौते पर पहुंच सकेंगे या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गत सप्ताह कहा कि उन्होंने करीब 12 देशों को शुल्क ब्योरे के साथ पत्र लिख दिए हैं जो सोमवार को भेज दिए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुल्क दर काफी अधिक (70 फीसदी तक) हो सकती है और यह 1 अगस्त से लागू होगी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि 9 जुलाई को तथाकथित जवाबी शुल्क पर स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद भी बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। एक तरह से इससे यह भी पता चलता है कि परिस्थितियां कितनी जटिल हैं। अमेरिका कई देशों के साथ व्यापार समझौते पर नहीं पहुंच सका है। जब तक स्थगन की अवधि में इजाफा नहीं किया जाता है तब तक अमेरिका की प्रमुख कारोबारी साझेदारों के साथ समझौते में नाकामी वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता को बढ़ाएगी।

जहां तक भारत की बात है, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के बीच समझौता कब तक होगा। जानकारी के मुताबिक भारत के वार्ताकार स्वदेश लौट चुके हैं। इसे संकेत मिलता है कि शायद भारत और अमेरिका 9 जुलाई की तय अवधि के पहले समझौता नहीं कर सकें। खबरें बताती हैं कि अमेरिका कुछ अन्य क्षेत्रों के अलावा कृषि जिंसों के मामले में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। भारत इन मांगों को लेकर सहज नहीं है। भारत की करीब आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। अमेरिका जीन संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना चाहता है। भारत में इसे लेकर भी चिंताएं व्याप्त हैं। इसके अलावा भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति हो। अमेरिका और वियतनाम के बीच हुए समझौते से कुछ संकेत ग्रहण किए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक यह एकदम एकतरफा समझौता है जिसके तहत अमेरिकी वस्तुएं तो बिना किसी शुल्क के वियतनाम में बेची जाएंगी लेकिन अमेरिका वियतनाम से आयातित वस्तुओं पर 20 फीसदी और ट्रांसशिपमेंट पर 40 फीसदी शुल्क लगाएगा। इस सौदे ने वैश्विक व्यापार समझौतों और स्वीकार्य मानकों को सिर के बल उलट दिया क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक अपेक्षाकृत छोटी और विकासशील अर्थव्यवस्था से अपने बाजार को बचाना चाहती है और वहां अपनी वस्तुओं की शुल्क मुक्त पहुंच चाहती है। भारत की अपनी जटिलताएं हैं और वह एक बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए उसका ऐसी शर्तों को स्वीकार करना मुश्किल है। इस देरी की यह भी एक वजह हो सकती है।

चूंकि बीते तीन महीनों में अमेरिका की ओर से कोई खास प्रगति नहीं हुई है इसलिए नई विश्व व्यवस्था अनिश्चित बनी रहेगी। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि अमेरिका उच्च शुल्क लगाएगा जिससे वैश्विक व्यापार की मुश्किलें बढ़ेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिका जल्दी ही साझा लाभ वाले समझौते पर पहुंचेंगे। भारत को अन्य कारोबारी साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे। यह न केवल इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अमेरिका ऐसा कर रहा है बल्कि चीन ने भी यह रुख अपनाया है। वह विनिर्माण और व्यापार में अपने दबदबे का प्रयोग अन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कर रहा है। हाल ही में उसने भारतीय मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र से अपने कुछ इंजीनियर वापस बुला लिए। जाहिर है वह इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को बाधित करना चाहता है।

ऐसे में भारत को न केवल अपनी क्षमताएं बढ़ाने पर विचार करना चाहिए बल्कि समान सोच वाले देशों के साथ काम करके विश्व व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था का भी बचाव करना चाहिए। साफ कहें तो भारत तथा कई अन्य देशों के लिए मौजूदा माहौल में वांछित तेजी से विकास मुश्किल है लेकिन संबद्धता और सहयोग बढ़ाने के तरीके तलाश करने होंगे।

कच्छ जंग के उदाहरण में छिपी भविष्य की आहट

कच्छ में हुई लड़ाई पाकिस्तान के साथ हमारी सबसे अधिक भुला दी जाने वाली जंग है, जबकि हकीकत यह है कि इससे सबक लेकर हमें अगले छह महीने, दो साल और पांच साल की योजना बनानी चाहिए।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

यह सही है कि केवल भारत ही ऑपरेशन सिंदूर को अधूरा काम बता रहा है लेकिन दोनों देश इसे केवल एक झलक के रूप में देख रहे हैं या फिर अगले दौर की तैयारी के रूप में। कोई भी इसे अंतिम नतीजे तक पहुंची लड़ाई नहीं मान रहा है।

उपमहाद्वीप का इतिहास बताता है कि यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 9 अप्रैल, 1965 को कच्छ में हुई झड़प का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की घोषणा की लेकिन इसके पांच महीने बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने कच्छ से गलत सबक लेकर युद्ध छेड़ दिया। उम्मीद करनी चाहिए कि छह दशक बाद अब वह समझदारी दिखाएगा। परंतु उम्मीद कोई योजना या रणनीति नहीं होती। पाकिस्तान के लिए हार स्वीकार करना आसान नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता या करगिल में स्पष्ट पराजय का मामला हमारे सामने है। अगर एकदम निर्णायक सबूत न हों तो आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी जीत की घोषणा करेगा। और एक बार जब वे खुद को 'दिखा हमने छोटा युद्ध जीत लिया' वाली मानसिक स्थिति में ले आते हैं तो इस बात की आशंका रहती है कि वे जल्द से जल्द हमला करेंगे।

इस समय दोनों पक्ष अपने-अपने सबक ले रहे हैं। जब मैं यह आलेख लिखने बैठा तो उसके कुछ ही घंटे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जो सेना के तीन उप प्रमुखों में से एक हैं, ने कुछ सबकों और भविष्य के लिए कुछ बिंदुओं पर बात की। यह अच्छा विचार है। कम से कम एक पक्ष यानी हम बिना दिमाग लगाए जीत की घोषणा न करते हुए आगे के बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। इसकी तुलना कच्छ से की जा सकती है। भारत ने कहीं अधिक समझदारी से और हकीकत के करीब रहते हुए सबक लिए थे और उसका नतीजा अगले युद्ध में रणनीतिक जीत के रूप में सामने आया। भारत के लिए रणनीतिक जीत इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का इरादा कश्मीर को हड़पने का था और उसी ने जंग छेड़ी। वह ऐसा नहीं कर सका और उसे हर मोर्चे पर वापस लौटना पड़ा। आक्रमण करने वाले देश को रक्षात्मक होना पड़ा जो भारत की रणनीतिक जीत थी। आखिर में अंतर उन सबक में ही रहा जो दोनों देशों ने कच्छ से ग्रहण किए थे। अगर पाकिस्तान कश्मीर पर दबाव बनाता तो भारत लाहौर और सियालकोट पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। यह तो तथ्यों में दर्ज है कि कच्छ के युद्ध विराम के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई बी चव्हाण, गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा और शीर्ष सैन्य कमांडरों ने जालंधर में 11वीं कोर के मुख्यालय में बैठक की थी। वहां जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी पंजाब में नए मोर्चे खोलने पर चर्चा हुई। इस योजना को ऑपरेशन रिडल का नाम दिया गया था। यह भारत के लिए कच्छ के बाद लिए गए सबक और तैयारी का हिस्सा था। इसे समझने के लिए तत्कालीन पश्चिमी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के वॉर डिस्पैच को पढ़ा जाना चाहिए। उस समय पश्चिमी कमान में जम्मू-कश्मीर भी शामिल था। कच्छ की लड़ाई को हमने भुला दिया है, जबकि यह लड़ाई 9 अप्रैल से 1 जुलाई तक चली थी जो लंबा समय है। ऑपरेशन सिंदूर तो केवल 87 घंटे चला। परंतु दोनों से मिले सबकों में समानता है।

पाकिस्तान ने जो सबक सीखा वह उसके सत्ता प्रतिष्ठान की बहुत बड़ी चूक साबित हुआ। उसने अनुमान लगाया था कि लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध विराम और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता स्वीकार करके हार मान ली है। यही वजह है उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिये कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की और उसके बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जरिये अखनूर को कब्जे में लेने और कश्मीर के अधिकांश हिस्से को काट देने की कोशिश की गई।

हम जहां शांति और स्थिरता की कामना करते हैं वहीं हमें इतिहास को ध्यान में रखना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व का मस्तिष्क उसके सिर में नहीं है। वह शरीर के किसी निचले हिस्से में है जिसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। जिस देश की शांति और प्रगति दांव पर हो उसे विरोधी के गलत कदम के लिए तैयार रहना चाहिए जो केवल सामरिक सोच में उलझा रहता हो। जैसा कि मैंने इसी स्तंभ के एक पिछले आलेख में कहा था कि आसिम मुनीर के पास सीमित समय है। भले ही पाकिस्तान की सेना देश पर काबिज रहेगी लेकिन खुद मुनीर का सेना पर स्थायी नियंत्रण नहीं है। समय के साथ यानी शायद अगले कुछ महीनों में उनकी असंवैधानिक और गैर संस्थागत शक्तियों को राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों से चुनौती मिल सकती है। सवाल यह है कि गैर संस्थागत से क्या तात्पर्य है? अतीत में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों ने संस्थागत रूप से सत्ता पर कब्जा किया है लेकिन इस अप्रत्यक्ष अधिग्रहण में मुनीर ने न केवल एक अतिरिक्त सितारा अर्जित किया है बल्कि एक व्यक्ति के रूप में राजनीतिक शक्ति भी हासिल की है। यह सब लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनका अधैर्य जल्दी सामने आएगा। वह ऑपरेशन सिंदूर से वैसे ही गलत सबक लेंगे जैसे उनके पूर्वजों ने कच्छ से लिए थे। शायद उन्हें लगेगा कि एक और झड़प की जा सकती है। भारत स्थिरता चाहता है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है और हम इस तरह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं कि अब लंबे संघर्ष का जोखिम नहीं उठाना चाहते। ऐसे में बड़ी शक्तियां सामने आएंगी। मुनीर सोचेंगे कि इस तरह के छोटे संघर्ष भारत को असंतुलित रखेंगे, कश्मीर घाटी को अस्थिर करेंगे लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह उनके अपने जन समर्थन को सुरक्षित रखेगा। मुनीर को लगता है कि उन्होंने भारत के खिलाफ दांव चल दिया है। कश्मीर में आतंकी हमला, उसके बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया और फिर कुछ दिन उथलपुथल। इससे इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण भी जारी रहेगा। उन्हें लगता है कि पहलगाम में उनका पहला कदम कायमबाव रहा और दुनिया भर का ध्यान आतंकवाद से परमाणु लड़ाई की ओर हो गया।

हम नहीं जानते कि ऐसा कब होगा लेकिन ऐसा होकर रहेगा। ऐसे में भारत को चरणबद्ध योजना बनानी होगी। छह महीने के लिए, दो वर्ष के लिए (उस समय तक अगले आम चुनाव करीब आ जाएंगे) और पांच साल के लिए। हमें अधिकतम पांच वर्ष की समय सीमा लेकर चलनी चाहिए।

छह महीने तक भारत को मिसाइल, गोला-बारूद, सेंसर और अन्य उपकरणों के मामले में अपनी कमी दूर करनी होगी। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाले एक्सकैलिबर श्रेणी के स्मार्ट तोपखाने, बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली का विकास आदि अहम हैं। साथ ही नौसेना के प्लेटफॉर्म्स को भी बेहतर बनाना होगा। इनमें से अधिकांश काम घरेलू स्तर पर किए जा सकते हैं और इसे युद्ध स्तर पर करना होगा।

मौजूदा तरीका नहीं काम करेगा जहां आज जरूरत की स्वीकृति के बाद 18 महीने परीक्षण में लग जाते हैं। याद रखें कि आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अगले दो साल में भारत को कम से कम दो बीवीआर (बियॉन्ड द विजुअल रेंज) लड़ाकू विमान हासिल करने होंगे। लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपखाने की बात करें तो उसमें सुधार की जरूरत है और उसे इस स्तर तक सुधारना होगा कि वह अपने आप में एक मजबूत प्रतिरोध बन जाए। इसे मोटे तौर पर देश में बनाकर कुछ स्मार्ट हथियार बाहर से खरीदे जा सकते हैं। इसमें गुणवत्ता और मात्रात्मकता दोनों शामिल होंगी। अगले पांच साल में हमें अपने रक्षा व्यय को भी बढ़ाना होगा। पहले तीन साल में उसे जीडीपी के 1.9 फीसदी से 2.5 फीसदी करना होगा और उसके बाद और इजाफा करने की जरूरत होगी। हम ऐसा कर सकते हैं। हमें इस संकल्प के साथ काम करना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष में एक पल के लिए भी पीछे न रहने पाएं। भले ही उसे चीन की मदद हासिल हो। इसके साथ ही हमें आर्थिक वृद्धि, कूटनीति और गठजोड़ों पर ध्यान देना होगा। इन सबके साथ ही अपनी सुरक्षा जरूरी है। इस सप्ताह के आरंभ में भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने एक कार्यक्रम में एक सलाह दी थी जिससे मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाइए और अर्थव्यवस्था को उदार बनाइए क्योंकि निवेशक तभी आएंगे जब उनको भरोसा होगा कि आपकी सुरक्षा मजबूत है।

अगर रणनीतिक रूप से इस समय को आरामतलबी में बिता दिया गया तो यह अक्षम्य भूल होगी। यह आगे बढ़ने का समय है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी एक बात है लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा है।

ग्राहक केंद्रित रणनीति में हो बेहतर लाभ पहुंचाने पर जोर

रमा बीजापुरकर

एक समय में 'कस्टमर सेंट्रिक' (ग्राहक-केंद्रित) शब्दावली बेहद लोकप्रिय थी लेकिन अब उसकी जगह तेजी से एक अधिक प्रभावशाली शब्द 'कस्टमर अबसेस्ड' (ग्राहक-जुनूनी या ग्राहक आसक्त) ले रहा है। यह शब्द अब बोर्डरूम प्रेजेंटेशन में, 'मोट' (बाजार में मजबूत पकड़) और 'पिवट' (दिशा बदलना) जैसे शब्दों के साथ, सबसे पसंदीदा बन गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 'ग्राहक-केंद्रित' और 'ग्राहक को लेकर जुनून' जैसी शब्दावली बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। वास्तव में, वे एक-दूसरे के लिए आईने जैसे हैं। 'ग्राहक-केंद्रित' शब्दावली के केंद्र में ध्यान ग्राहकों की दुनिया पर होता है जबकि 'ग्राहक के प्रति जुनून' का केंद्र मार्केटिंग करने वालों की दुनिया पर होता है।

सेमीकंडक्टर कंपनी एएमडी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हेक्टर रुइज के अनुसार, ग्राहक केंद्रित रणनीति की एक बहुत अच्छी परिभाषा यह है कि ग्राहक जो कुछ भी चाहता है, वह सब कुछ न करने के बजाय ग्राहक के फायदे के लिए हर काम करना। बेशक, इसे ऐसे तरीके से करना जिससे कंपनी को खुद भी फायदा हो। ग्राहक केंद्रित रणनीति का मतलब यह समझना है कि हम अपने ग्राहक के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, जो ग्राहक को सच में महसूस हो। यह वह फायदा नहीं है जो मार्केटिंग वाले सोचते हैं कि ग्राहकों को मिलना चाहिए। वहीं, ग्राहक के प्रति जुनून का मतलब अक्सर यह होता है कि ग्राहक से अधिक से अधिक पैसे कैसे कमाए जाएं।

कई बार कंपनियों की प्रेजेंटेशन में ऐसी स्लाइड दिखती है जिस पर लिखा होता है 'हममें ग्राहकों को अपनाने के लिए जुनून है'। इसमें ग्राहक को केंद्र में रखकर दिखाया जाता है कि कौन से तरीके अपनाए जाएं जिनसे कंपनी ग्राहक की जेब से और पैसा निकाल सके, जैसे उन्हें और चीजें बेचना, अधिक महंगी चीजें बेचना या उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की तरकीबें। इसमें यह नहीं दिखता कि कंपनी ग्राहक के लिए क्या करेगी। इसमें ऐसी बहुत सी भ्रामक, 'ग्राहक केंद्रित' बातें लिखी होती हैं जैसे 'हम ग्राहकों को खुश कर देंगे' या 'हम दुनिया भर में ग्राहकों के पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बनेंगे।' ये सारी बातें सिर्फ कंपनी के बारे में होती हैं, इनमें से एक भी शब्द यह नहीं बताता कि वे ग्राहकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे।

ग्राहकों के साथ बार-बार उत्पादों की जांच करना भी ग्राहक केंद्रित रणनीति नहीं है बल्कि यह उत्पाद केंद्रित रणनीति है यानी, सिर्फ उत्पाद पर ध्यान देना। ग्राहकों से बार-बार यह पूछना कि किसी उत्पाद या सेवा से उनकी क्या उम्मीदें हैं (और फिर शिकायत करना कि ग्राहकों को नहीं पता), यह भी ग्राहक केंद्रित रवैया नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप फैसले लेने की जिम्मेदारी ग्राहकों पर छोड़ रहे हों और उन्हें ही कंपनी का मार्केटिंग निदेशक बना रहे हों। ग्राहक का काम तो अपनी समस्या या परेशानी बताना है, या यह समझना है कि उनके लिए कौन सी चीज फायदेमंद है (यानी, एक अंदरूनी प्रक्रिया जिससे वे तय करते हैं कि कौन से फायदे वास्तव में उनके लिए मूल्यवान हैं)।

ग्राहकों का काम अपनी समस्या या परेशानी को हल करने के लिए उपाय खोजना या यह बताना नहीं है कि कंपनियां उन्हें और कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या किया जा सकता है। ग्राहकों को बस इतना पता है कि क्या करने से उन्हें अधिक खुशी मिलेगी। ग्राहक-केंद्रित कंपनियां वही करने के लिए लगातार मेहनत करती हैं। वे समझती हैं कि आज ग्राहक किन बातों पर समझौता कर रहे हैं, जैसे एक तीन-सितारा सस्ते होटल में ठहरने से उन्हें कोई खास एहसास नहीं होता है जबकि पांच-सितारा होटल उन्हें खास महसूस कराता है। हालांकि पांच-सितारा होटल बहुत महंगा होता है और उनकी जरूरत से अधिक सुविधाएं देता है। या फिर दूरदराज के इलाके में रहने वाला कोई छोटा ग्राहक जिसे कुछ खास चीजें खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। वे कंपनियां ऐसे मजबूरी के समझौतों को खत्म करने और ग्राहकों को मिलने वाले असली फायदे को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं। ग्राहक केंद्रित होने का मतलब है कि अपने कारोबारी फैसले और योजना को इस सोच पर लाना कि 'हम ग्राहकों के लिए क्या कर सकते हैं?'

नई अर्थव्यवस्था की कई (सभी नहीं) स्टार्टअप कंपनियां जिनके डिजिटल कारोबारी मॉडल हैं, उन्होंने बड़ी कंपनियों के मुकाबले कहीं अधिक ग्राहक केंद्रित रवैया दिखाया है। उन्होंने इसमें कामयाबी पाई है कि ग्राहकों को किसी चीज से मजबूरी में समझौता न करना पड़े। साथ ही, उन्होंने भारतीय बाजार की एक मुश्किल चुनौती भी हल की है, मसलन जहां ग्राहक अच्छी गुणवत्ता बेहद कम दाम पर चाहते हैं और कंपनियां हर इकाई पर ठीक-ठाक मुनाफा कमाना चाहती हैं। स्टार्टअप कंपनियों ने लोगों और कारोबारों की समस्याओं को हल करने या उन्हें फायदा पहुंचाने वाले समाधान बनाने में पारंपरिक मार्केटिंग से कहीं अधिक ग्राहक-केंद्रित रवैया दिखाया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें फंडिंग करने वाले लगातार पूछते हैं, 'आप सफल कैसे होंगे?' यह बात उन्हें ग्राहकों की अनसुलझी समस्याओं पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं, पारंपरिक मार्केटिंग आज 'प्रदर्शन वाले मार्केटिंग मॉडल' यानी कितने उत्पाद या सेवाएं बेची गईं उन पर अधिक ध्यान देती है न कि ग्राहकों के लिए असली फायदा बनाने या उसे देने (या उसे खोजने) पर। शोध एवं विकास (आरएंडडी) करने वाले लोग भी अक्सर मार्केटिंग वालों से अधिक ग्राहक-केंद्रित होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनका काम ही समस्याओं को हल करना या इस्तेमाल के लिए बेहतर चीजें बनाना है। अगर हम डिजिटल इंटरफेस को डिजाइन करने की बात करें तो यूआई यूएक्स विशेषज्ञों के होते हुए भी ग्राहक केंद्रित रणनीति के कई स्तर या प्रकार दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंकों के ऐप जो शायद तकनीकी रूप से तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐप खोलते ही आपका काम पूरा करने से पहले ही आपको दूसरी चीजें बेचने लगते हैं। ऐसा लगता है वहां ग्राहकों को अपनी जद में करने वाले ग्राहकों के जुनूनी आपूर्तिकर्ताओं की भरमार है जिनका मानना है कि ग्राहक का काम जल्द से हो जाए उसकी तुलना में बैंक का काम अधिक जरूरी है। अगर गलती से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के तकनीशियन ग्राहकों को मेसेज भेजने का काम संभाल लें, तब हमें ऐसे संदेश मिलते हैं, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अब वापस ऑनलाइन हो गए हैं' जबकि उन्हें कहना चाहिए, 'हमें आपकी इंटरनेट सेवा में आई रुकावट और उससे हुई परेशानी के लिए खेद है। हम अब ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए तैयार हैं।'

ग्राहक केंद्रित रवैये का मतलब लंबे, समय बर्बाद करने वाले फीडबैक फॉर्म भरवाना या सीईओ के बोनस को 'शुद्ध प्रवर्तक स्कोर' से जोड़ना नहीं है। इसका मतलब यह सोचना है, 'मैं ग्राहकों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं?' जैसा वे खुद समझते हैं, न कि जैसा मैं समझता हूं और 'मैं इसे कैसे बेहतर तरीके से करूं, जिससे उन्हें अधिक फायदा हो और मुझे कम से कम खर्च आए?'

(लेखिका ग्राहक आधारित कारोबार रणनीति के क्षेत्र में एक कारोबारी सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

वैज्ञानिक सोच को नीतियों के केंद्र में लाना समय की मांग

उच्च माध्यमिक की पढ़ाई के दौरान ही शोधार्थी विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए। 20वीं सदी में अमेरिका के महाशक्ति बनने के पीछे उसकी विज्ञान केंद्रित नीतियों की निर्णायक भूमिका रही। नैशनल साइंस फाउंडेशन और डीएआरपीए जैसे संस्थानों के माध्यम से अमेरिका ने रक्षा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दूरदर्शी निवेश किया, जिससे न केवल समृद्धि के नए द्वार खुले, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व भी स्थापित हुआ। आज चीन भी इसी राह पर चलते हुए शोध एवं विकास को प्राथमिकता देकर तकनीकी महाशक्ति बन चुका है। इसके विपरीत भारत में शोध का उद्देश्य प्रायः डिग्री प्राप्ति तक सीमित रह गया है। विषय चयन, अध्ययन पद्धति और शोध की दिशा अक्सर व्यावहारिक परिणाम देने में विफल रहती है। ऐसे में समय आ गया है कि हम अपने शैक्षणिक ढांचे में

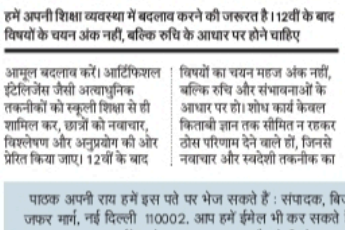

हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। 12वीं के बाद विषयों के चयन अंक नहीं, बल्कि रुचि के आधार पर होने चाहिए

आमूल बदलाव करें। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को स्कूली शिक्षा से ही शामिल कर, छात्रों को नवाचार, विश्लेषण और अनुप्रयोग की ओर प्रेरित किया जाए। 12वीं के बाद विषयों का चयन महज अंक नहीं, बल्कि रुचि और संभावनाओं के आधार पर हो। शोध कार्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर ठोस परिणाम देने वाले हों, जिनसे नवाचार और स्वदेशी तकनीक का विकास हो सके। यदि हम विज्ञान को नीति-निर्माण का मूल आधार बनाएं और युवा प्रतिभा को आधुनिक उपकरणों और अवसरों से जोड़ें, तो भारत भी विज्ञान के पथ पर चलते हुए आत्मनिर्भरता, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

नीति आयोग दीर्घकालिक योजनाओं तक सीमित रहे

खाद्य शुल्कों में कटौती जोखिम भरा दांव' केंद्र सरकार को अमेरिका के साथ खाद्य वस्तुओं के आयात निर्यात में शुल्क व्यवस्था पर सचेत करता है। इसके साथ यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या नीति आयोग केंद्र सरकार के कृषि और वाणिज्य मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र में समानांतर नीति निर्धारण के लिए सक्षम है और क्या उसके पास इस व्यापार समझौते के लिए उचित और प्रासंगिक डेटा है? क्या यह आवश्यक और न्यायोचित नहीं है कि खाद्य विषयों पर कृषि और वाणिज्य मंत्रालय ही किसानों और खाद्य पदार्थों के उत्पादकों और व्यापारियों के हितों की समन्वित रूप से रक्षा करते हुए अमेरिका के समक्ष स्पष्ट रूप से अपना पक्ष सामने रखें भी और उस पर दृढ़ भी रहें। इस विश्व की अमेरिका और चीन नहीं चला रहे बल्कि दोनों देश वैश्विक व्यवस्थाओं को बाधित कर रहे हैं और विघ्न डाल रहे हैं। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में नीति आयोग ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी, फिर अमेरिका के लिए इतनी व्याकुलता क्यों? जिस देश में 80 फीसदी जनता परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है उस पर अमेरिका का वर्चस्व कैसे हो सकता है? डॉनल्ड ट्रंप व्यापारी की तरह व्यापार समझौते कर रहे हैं लेकिन हम उनकी मंडी नहीं हैं। नीति आयोग को दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई मुंबई के गिरगांव स्थित अपने विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से मुलाकात की और वहां उपस्थित विद्यार्थियों के साथ भी संवाद किया।

हिन्दुस्तान 1936

मन का मित्र एआई

कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की दुनिया में नित नए शोध और खोज का सिलसिला जारी है। यह किसी खुशखबरी से कम नहीं कि जर्मनी की शोध संस्था हेल्महोल्ट्ज म्यूनिख ने सेंटों नाम के एक ऐसे एआई मॉडल का विकास किया है, जो न केवल इंसानों की तरह सोचता है, बल्कि प्रतिक्रिया भी देता है। अन्य एआई मॉडल से यह इसलिए अलग है, क्योंकि परिचित कामों में इंसानी व्यवहार का अनुमान लगाने के साथ ही यह पूरी तरह से नए हालात में भी इंसानी व्यवहार का आकलन करने में प्रायोगिक रूप से सफल साबित हुआ है। कहा जा सकता है कि यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने का प्रयोग है। नेचर पत्रिका में छपे अध्ययन में कहा गया है कि इसे विकसित करने के लिए मनोविज्ञान से जुड़े 160 प्रयोगों का उपयोग किया गया, जिनमें 60,000 लोगों ने कई परिस्थितियों के संदर्भ में एक करोड़ से अधिक विकल्प तैयार किए। यानी, इस एआई मॉडल सेंटों के पास इंसानों द्वारा सोचे जा सकने वाले एक करोड़ से अधिक विचारों का संग्रह है, जिसका विश्लेषण करते हुए यह समाधान पेश कर सकता है।

जाहिर है, सेंटों का व्यावहारिक पक्ष काफी कारगर साबित होने वाला है। शोधकर्ताओं की मानें, तो इसका विशेष उपयोग अवसाद से जुड़ी बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है। उनके मुताबिक, यह एआई मॉडल स्वास्थ्य अनुसंधान की दिशा में एक नई राह तैयार करता है, जिससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्थितियों वाले लोग किस तरह फैसले लेते हैं। इससे मनोरोगियों के इलाज में काफी सहायता मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर मार्सेल बिंस और डॉ एरिक शुल्ज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम पूरी तरह आश्वस्त है और उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसका उपयोग यह पता लगाने में भी किया जाएगा कि स्वस्थ व्यक्तियों और मनोरोगियों में फैसले लेने की आंतरिक दिमागी रणनीति किस कदर अलग होती है? यह प्रयोग जब आगे बढ़ेगा, तब मानव अनुभूति की हमारी समझ और बेहतर हो सकेगी।

सेंटों नामक एआई मॉडल अवसाद से जुड़ी बीमारियों के इलाज में काम आ सकता है। इसके विकास से स्वास्थ्य अनुसंधान की दिशा में एक नई राह तैयार हो रही है।

अगर इस तरह के मॉडल विकसित होते हैं, तो भारत जैसे देशों के वे काफी काम आ सकते हैं। अनुमान है कि अपने देश में करीब 19.73 करोड़ लोग किसी-न-किसी मनोरोग से जूझ रहे हैं। विडंबना है कि ज्यादातर आबादी की पहुंच मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं है। आम लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिहाज से 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत जरूर की गई, लेकिन इसे मनमाफिक सफलता नहीं मिल सकी है। भारतीय समाज में मनोरोगियों को आज भी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। जागरूकता का इस कदर अभाव है कि कई इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वाले लोग सामाजिक कलंक और भेदभाव से पीड़ित रहते हैं। नतीजतन, अपने यहां मानसिक बीमारियों को भरसक छिपाने की कोशिश होती है। पढ़े-लिखे तबके तक में इसको लेकर उदासीनता पसरी हुई है। ऐसी सूरत में, नई तकनीकें हमारे काफी काम आ सकती हैं। सेंटों जैसे एआई मॉडल मनोरोगियों के दिमागी संतुलन या उनकी सोचने-समझने की क्षमता का आकलन कर उनके इलाज में मदद कर सकेंगे। चिकित्सा जगत में सेंटों जैसे एआई मॉडलों की बड़ी जरूरत है और उनका समय के साथ कारगर होते चले जाना मानवता के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 जुलाई 1950

शांति के लिए खतरा

आज सारे संसार की आंखें कोरिया पर लगी हुई हैं, जहां विगत 12 दिनों से युद्ध की आग धधक रही है और उत्तरी भाग की साम्यवादी सेनाएं, अमरीकी हस्तक्षेप के बावजूद दक्षिणी फौजों को पराजित करती हुई निरन्तर आगे बढ़ रही हैं। रणक्षेत्र से प्राप्त ताजा समाचारों की ध्वनि यह है कि दक्षिणी सेनाओं की कमर पूर्णतया टूट चुकी है और अब लड़ाई का मुख्य भार अमरीकी सेनाओं के कंधों पर ही रह गया है। इस बीच में दक्षिण कोरिया की री-सरकार ताएजोन से चेंजू चली गई बताते हैं, जो वहां से 50 मिल दक्षिण-पश्चिम में है। इस घटनाक्रम से प्रश्न उठता है कि क्या कोरिया की चीन जैसी ही हालत होगी?

हम अभी इस सम्बन्ध में कि मैदान किसके हाथ रहेगा, कुछ नहीं कह सकते; किन्तु, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि अमरीका अपने समस्त बल से लड़ाई में न कूदा होता और सुरक्षा-परिषद ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी न ठहराया होता तो अब तक री-सरकार का कहीं पता न चलता और समूचा कोरिया साम्यवादियों के अधिकार में हो जाता। अमरीका के हस्तक्षेप से स्थिति बदल गयी है और लड़ाई के लम्बी होने की सम्भावना बढ़ गई है। हमारे खयाल में इस लड़ाई के तूल पकड़ने से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न होने के अतिरिक्त तीसरे महायुद्ध की आशंका भी बढ़ सकती है; क्योंकि आज तो सोवियत रूस इस मामले में चुप बैठा हुआ है, परन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि वह कल भी इस विषय में तटस्थ बना रहेगा। किसी को स्वप्न में भी खयाल नहीं था कि अमरीका दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए इतनी दृढ़ता से काम लेगा।

यद्यपि हम दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण को बुरा मानते हैं, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमन के ऐतिहासिक निश्चय के पीछे एक बड़ा रहस्य है। वह यह कि चीन में चांगकाई शेक की पराजय व साम्यवादियों की विजय के बाद अमरीका पूर्णरूपेण सजग हो गया है और वह चाहता है कि साम्यवाद को आगे पैर न फैलाने दे। इसी कारण से अमरीका में आज कोरियाई युद्ध को "साम्यवाद के विरुद्ध धर्मयुद्ध" कहा जा रहा है। यहां के आइसनहोवर जैसे उच्च कोटि के सैनिक नेता भी अमरीकी जनता से प्रस्तुत युद्ध को जीत लेने के लिए कह रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के सफल ग्यारह साल

यहां स्कैन करें

जगत प्रकाश नड्डा | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

यह आंकड़े बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी 'यूएन-एमएमईआईजी' के मुताबिक, भारत में मातृ मृत्यु दर में 86 फीसदी, तो शिशु मृत्यु दर में 73 प्रतिशत की कमी आई है।

पिछले ग्यारह वर्षों में भारत की स्वास्थ्य-व्यवस्था में जबर्दस्त परिवर्तन आया है। यह बदलाव मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, अधिक फंडिंग और सभी को सस्ती, सुलभ व अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प के कारण संभव हो पाया है। यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसमें हर नागरिक की भलाई को प्राथमिकता दी गई है।

साल 2014 तक देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें आधारभूत संरचनाओं की कमी, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता में अंतर, दवाइयों व जांच सुविधाओं की सीमित पहुंच और सेवा की गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। आज समग्र देखभाल- रोगों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और गंभीर बीमारियों की देखभाल-की अवधारणा के तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। नवाचारी कार्यक्रमों, रणनीतिक निवेश और जन-केंद्रित दृष्टिकोण इस परिवर्तन की पहचान रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस क्रांति की आधारशिला रहा है, जिसने स्वास्थ्य-तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने; बीमारियों से लड़ने और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में सहायता की। सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में, 1.77 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के और करीब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर अब तक 427.57 करोड़ बार मरीज आ चुके हैं, 5.5 करोड़ स्वास्थ्य-सत्र आयोजित किए जा चुके हैं और 36.64 करोड़ 'टेली-कंसल्टेशन' हुए हैं। ई-संजीवनी और टेली-मानस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दूर-दराज के लोगों को भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लक्षित प्रयासों की वजह से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की मातृ मृत्यु दर पर निगाह रखने वाली संस्था 'यूएन-एमएमईआईजी' के मुताबिक, भारत में मातृ मृत्यु दर में 86 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 48 फीसदी की वैश्विक औसत गिरावट से लगभग दोगुनी है। बच्चों के स्वास्थ्य में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। शिशु मृत्यु दर में 73 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 58 फीसदी रही।

गैर-संचारी रोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए अब सिर्फ इलाज नहीं, रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मुंह, छाती और सर्वाइकल कैंसर की जांच उपलब्ध हैं। मई 2025 तक, लगभग 28 करोड़ लोगों की उच्च रक्तचाप, 27 करोड़ लोगों की डायबिटीज और 27 करोड़ लोगों की मुंह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हुई है। बीमारियों की जल्द जांच व समय पर इलाज से अब स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हुए हैं और रोगों का भार भी घट रहा है।

टीकाकरण कार्यक्रम भी लगातार मजबूत हो रहा है। 2014 के बाद से छह नए टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत टीकाकरण का दायरा बढ़ा है। इसके अंतर्गत 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है। एक अहम कदम के रूप में, यू-विन पोर्टल के जरिये टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल किया गया है। साल 2026 तक हम खसरा-रूबेला का उन्मूलन करने के लिए तैयार हैं।

रोग-उन्मूलन में भी भारत ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। साल 2014 में भारत को पोलियो-मुक्त घोषित किया गया। वहीं, 2015 में मातृ और नवजात टेटनस व 2024 में ट्रेकोमा का उन्मूलन भी हो चुका है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई। हमने सतत विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित वैश्विक 2030 लक्ष्य से पहले ही वर्ष 2023 में कालाजार के उन्मूलन के लिए तय मानकों को प्राप्त कर लिया है।

हमारे सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत की कमी और मृत्यु दर में 21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024' में की गई है। 'मिसिंग' टीबी मामलों की संख्या भी साल 2015 के 15 लाख से घटकर 2024 में केवल 1.2 लाख रह गई है।

परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के वित्त-पोषण में सुधार किया गया है। 2014-2022 के बीच सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के 1.13 प्रतिशत से बढ़कर 1.84 प्रतिशत हो गया है। वहीं, लोगों की जेब से होने वाले खर्च में विशेष गिरावट आई और यह 62.6 फीसदी से घटकर 39.4 फीसदी रह गया है। 'मुफ्त दवा और जांच सेवा' ने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया है। अभी 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में जांच सेवाएं उपलब्ध हैं। 34 राज्यों में सीटी स्कैन सुविधा है, तो 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में टेली-रेडियोलॉजी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' से 28 लाख से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं, जिससे उनके खर्च में 8,725 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना आवश्यक है। इसी लक्ष्य के साथ साल 2021 में 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' शुरू किया गया। इसकी मुख्य पहल में 18,802 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों और 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना शामिल हैं। मानव संसाधन, एक मजबूत स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका इन 11 वर्षों में विस्तार ऐतिहासिक रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 5.23 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया है, जिनमें 1.18 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) भी शामिल हैं। इसने समुदायों के करीब गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के माध्यम से गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

पिछले 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य क्रांति ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य-सेवा की मजबूत नींव रखी है। सशक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, निरंतर प्रयास, नवाचार और जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, आज देश सभी के लिए सुलभ, किफायती और समतामूलक स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डॉलर के कमजोर पड़ने का हमें लाभ उठाना चाहिए

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले पचास साल में जो नहीं हुआ, वह हो रहा है। और वह भी तब हो रहा है, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता अपने देश को फिर से महान बनाने के अभियान में सारे घोड़े खोलकर चतुर्दिक पताका फहराने के काम में जुटे हुए हैं। जी हां, 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन', यानी मागा के दौर में अमेरिकी डॉलर लगातार गिरता जा रहा है। भारत में डॉलर के सामने रुपये का हिसाब जोड़ने वालों को भले ही बात उतनी गंभीर न लग रही हो, मगर अंतरराष्ट्रीय कारोबार में यह बड़ी चिंता का कारण बन चुका है।

सन् 1973 के बाद से डॉलर में गिरावट का यह सबसे तेज और लंबा सिलसिला है। इस साल की शुरुआत से अब तक डॉलर में करीब दस प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। छह महीने में इतनी बड़ी गिरावट कोई मामूली बात नहीं है। अमेरिकी मुद्रा ने इससे पहले ऐसे बुरे दिन आखिरी बार 1973 में देखे थे। हालांकि, इसका असर यह भी हो सकता है कि अमेरिका से एक्सपोर्ट बढ़ाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना जल्दी पूरा हो जाए। मगर यह अमेरिका के लिए कितना लाभदायक होगा, कहना मुश्किल है।

सन् 73 के बाद से डॉलर में यह सबसे तेज गिरावट है। इस साल की शुरुआत से अब तक डॉलर में करीब दस प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

ज्यादातर जानकारों का कहना है, डॉलर की इस कमजोरी की सबसे बड़ी वजह ट्रंप की टैरिफ नीति और उनसे पैदा हुए हालात ही हैं। जाहिर है, टैरिफ का सीधा अर्थ है, देश में आने वाले सामान पर लगने वाला सीमा शुल्क। भारत में इसको आयात शुल्क कहा जाता था। असर भी साफ है। जो चीजें किसी दूसरे देश में पैदा होती या बनती हैं, अगर उन पर टैरिफ लगाया या बढ़ाया जाएगा, तो उनकी कीमत बढ़ेगी, यानी खरीदार की जेब पर बोझ पड़ेगा। इसीलिए, टैरिफ के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है और इसकी अर्थव्यवस्था पर मंडराते मंदी के बादल भी गहरा गए हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर यही हासिल करना चाहते थे? ऐसा कतई नहीं है। दरअसल, अमेरिका दुनिया के अनेक देशों के सामान का सबसे बड़ा खरीदार है। इसीलिए उनके सलाहकारों को और शायद खुद उन्हें भी उम्मीद थी कि जब अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव बढ़ाएगा और उनसे आयात के रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा, तो इन देशों के व्यापारी ही नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था भी दबाव में आएगी और उनकी मुट्ठियां कमजोर हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए उनसे सौदेबाजी करना आसान हो जाएगा। मगर हुआ इसके उलट। सबसे पहले तो जो भी अमेरिकी कारोबारी बाहर से सामान मंगाकर बेचते थे, उन्होंने टैरिफ लगने के ठीक पहले बड़े बड़े स्टॉक मंगाकर गोदाम भर डाले, ताकि दाम बढ़ने के झटके को टाला जा सके। इसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में डॉलर की आपूर्ति बढ़ गई और भाव गिरने लगा।

इसका क्या असर हो रहा है, इसका अंदाजा भारत में बैठकर भी लगाया जा सकता है। जब भी रुपये की कीमत गिरती है, तो यहां किस-किस तरह की चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो विदेश जाना या विदेश में खर्च करना महंगा पड़ने लगता है। अमेरिकी लोग भारतीयों के मुकाबले कहीं ज्यादा घुमक्कड़ होते हैं। उनका सैर-सपाटे का खर्च बढ़ गया है। हालांकि, ऐसे खर्च करने वाले ज्यादातर लोगों को शायद महंगाई की फिक्र कम होती है, भले ही जेब पर बोझ बढ़ रहा हो।

संकट सिर्फ महंगाई का नहीं है, महंगाई की वजह से आर्थिक प्रगति की रफ्तार थमने का भी है, क्योंकि बाजार में मांग घटेगी, तो उसका असर व्यापार, कारोबार और उद्योग सभी पर पड़ना तय है। जाहिर है, अमेरिकी सरकार को भी अब यह चिंता सामने दिख रही है। शायद इसीलिए ट्रंप प्रशासन एक के बाद एक व्यापार समझौता करने के मूड में भी दिख रहा है। लेकिन इतना तय है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मसले पर अमेरिका अब तलवार की धार पर चल रहा है। जहां एक तरफ उसे अपने उद्योगों और अपने लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे देशों को दबाव में लाते-लाते कहीं वह खुद के लिए ही मुसीबत न खड़ी कर ले। भारत जैसे देशों के लिए यहां एक बड़ा मौका है कि अमेरिका के साथ बातचीत में अपने हितों का पूरा खयाल रखते हुए, व्यापार और कारोबार के नए रिश्तों की मजबूत बुनियाद तैयार की जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

गुनगुनाना भी एक औषधि

एक पायलट ओशो से मिलने आया और उसने बताया कि वह जब हवाई जहाज को उड़ाता है, तो नादब्रह्म, ध्यान में जो गूंजर (हमिंग) कहा गया है, उसे गुनगुनाता है। उसने कहा, मुझे यह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत लगता है, इससे मैं तरोताजा अनुभव करता हूं।

ओशो ने कहा, हां, यह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। हम अपने स्वयं के स्रोतों को नहीं जानते और नहीं जानते कि उन स्रोतों से कैसे जुड़ें? जब आप कोई ध्वनि गुनगुनाते हैं, तो स्वयं के साथ एक सुरीले सामंजस्य में आ जाते हैं। ध्वनि आपके शरीर/मन में एक कंपन बन जाती है और धीरे-धीरे शरीर व मन एक तालमेल में आ जाते हैं। उनका संघर्ष समाप्त हो जाता है; संघर्ष की उस समाप्ति से ऊर्जा बच जाती है। आपकी ऊर्जा लगातार बर्बाद हो रही है, क्योंकि निरंतर संघर्ष है मन और शरीर के बीच। शरीर एक काम करना चाहता है, मन कुछ और करना चाहता है। एक पल मन यह कहता है, दूसरे पल वह करना चाहता है। इस टकराहट से कुछ भी हासिल नहीं होता, उल्टे आप थक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तभी कुछ हासिल कर सकता है, जब उसके भीतर सारे हिस्से एक लय में काम करते हों, कहीं कोई खींचातानी न हो।

गुनगुनाना मस्तिष्क के लिए कई लाभ प्रदान करता है, मुख्य रूप से यह वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है, जिससे तनाव कम हो सकता है, मूड बेहतर हो सकता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। यह सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे लाभकारी न्यूरो-ट्रांसमीटर का रिसाव बढ़ाता है, जिससे शांति और सुकून मिलता है। यदि आप ध्वनि की गुनगुनाहट जारी रखें, तो आप भूल जाएंगे कि थकान क्या होती है? आप एक अलग ही ताजगी अनुभव करेंगे। आप विश्राम करना तो चाहेंगे, लेकिन ऊर्जा रिसेगी नहीं, आप एक मीठी शिथिलता से घिरे होंगे। अपने काम से प्रेम करें। यह सबसे बढ़िया उपाय है, सकारात्मक ऊर्जा बनाने का। प्रेम हर चीज को शक्तिशाली बनाता है।

पायलटों के लिए शरीर और मन, दोनों का स्वास्थ्य अति आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन प्रायः मन के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता। यह ध्यान उन्हें बहुत सघन ऊर्जा देगा, क्योंकि वे

जब आप कोई ध्वनि गुनगुनाते हैं, तो स्वयं के साथ एक सुरीले सामंजस्य में आ जाते हैं। शरीर और मन का संघर्ष समाप्त हो जाता है; संघर्ष की उस समाप्ति से ऊर्जा बच जाती है।

गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ऊर्जा सरलता से ऊपर की दिशा में उठ सकती है। चारों तरफ आकाश का असीम विस्तार, बादलों के ऊपर सूरज का सफर, ये सब माहौल ध्यान के लिए बहुत अनुकूल है।

पायलट हमेशा जीवन और मौत के बीच रहता है। उसे बहुत ही सावधान रहना होता है। अगर वे पूरी सजगता से आंतरिक ऊर्जा से भरे हों, तो स्वभावतः उनमें आत्म-विश्वास अधिक होगा और खतरे के समय वह अधिक फुर्ती से सोच पाएंगे, ताकि दुर्घटना से बच सकें।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

दुनिया को बेहतर बनाने का हमारा वादा खतरे में है। विकास के लिए वित्त-पोषण सम्मेलन का उद्देश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए हमें इसे गति देनी होगी और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा।

वर्षों बाद रेल किराया बढ़ना गलत नहीं

हर महीने की शुरुआत कई बदलावों के साथ होती है और 1 जुलाई, 2025 का आगाज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनमें रेलवे में हुआ बदलाव खास है, क्योंकि आलोचकों की नजर में यह यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाला है। उनकी मानें, तो रेल किराये में हुई नई बढ़ोतरी यात्रियों पर खुब आर्थिक बोझ बढ़ाएगी और वे इससे सब हलकान हो जाएंगे।

हालांकि, रेल किराये में अभी जो बढ़ोतरी हुई है, वह लंबी दूरी की गाड़ियों में ही है। 500 किलोमीटर से कम साधारण दर्जे की यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इनमें भी एसी और नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की तमाम ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के मुताबिक, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराये में एक पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इन्हीं गाड़ियों की एसी श्रेणी में यात्रा करने पर यात्रियों को दो पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त किराया देना होगा। रेलवे की ओर से पहले ही यह साफ कर दिया गया है कि 500 किलोमीटर तक की रेल यात्रा के लिए सेकंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और मासिक टिकटों (एमएसटी) में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, इनके लिए किराया जस का तस रहेगा। हालांकि, अगर यात्री 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसे प्रति किलोमीटर आधा पैसा (0.5 पैसा) ज्यादा देना होगा। इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए, दिल्ली से पटना करीब 1,000 किलोमीटर है। अभी तक राजधानी ट्रेन में सफर करने पर किराया 2,485 रुपये था, जो 1 जुलाई से बढ़ोतरी के बाद 20 रुपये अधिक हो गया है। इसी तरह अन्य गाड़ियों के भी वातानुकूलित श्रेणी में यह किराया 20 रुपये बढ़ गया है।

मेरी समझ में इस किराये-वृद्धि में कोई बुराई नहीं है। रेलवे घाटे में ही चल रहा है, जिसकी जानकारी टिकट पर दी जाती है। फिर, जब देश में कर्मचारियों के वेतन-भत्ते हर साल बढ़ रहे हैं, महंगाई हर साल बढ़ रही है, तब रेल किराये में यह मामूली वृद्धि गलत नहीं लगती। पिछले कई वर्षों से मुझे याद नहीं कि रेल किराया बढ़ा हो। आखिर जो लोग एसी जैसी महंगी यात्रा के लिए सहर्ष टिकट कटाते हैं या एजेंटों को कई सौ रुपये अतिरिक्त देकर टिकट लेते हैं, उन्हें दस-बीस रुपये अधिक देने में हिचकना नहीं चाहिए। उनकी यह छोटी सी राशि रेलवे के खाते में जाने वाली है, न कि एजेंटों की जेब में। उम्मीद यही है कि रेलवे इन पैसों का सदुपयोग करेगा और यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेनों की संरक्षा बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगा।

सुधांशु कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
रेल किराया

सुविधाएं बढ़ाए बिना यह बढ़ोतरी अनुचित

रेलवे ने टिकट के दाम बढ़ाकर गरीब यात्रियों पर बोझ बढ़ा दिया है। बेशक, वे सुनने में मामूली बदलाव लगते हैं, लेकिन व्यापकता में देखेंगे, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल, हमारे नीति-नियंता वास्तविक स्थिति नहीं समझ रहे हैं। हमारे देश में रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की होती है, जो विपन्न हैं। ऐसे लोगों के लिए एक-एक रुपया बचाना भी अहम होता है। ऐसे लोग देश के सुदूर इलाकों से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब आदि बड़े राज्यों में काम की तलाश में जाते हैं। उनके लिए किसी भी तरह की सुविधा बढ़ाए बिना किराया बढ़ा देना गैर-वाजिब है।

दिक्कत यह भी है कि ये यात्री ऐसे बेजुबान होते हैं कि इस तरह के किसी अन्यायपूर्ण कदम का विरोध तक नहीं कर पाते। रेलवे स्टेशनों पर दलाल आदि इनसे पैसे ऐंठते दिखते हैं। कई बार तो उन्हें ट्रेनों में बैठने की सीट दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि रेलगाड़ियों में सामान्य डिब्बे लगातार कम किए जा रहे हैं, जबकि बेरोजगारों और काम की तलाश में दूर-दूर तक भटकने वाले मजदूरों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब तो ट्रेनों में सामान्य दर्जे के कमोबेश दो-तीन डिब्बे ही दिखते हैं। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी हाई-फाई कही जाने वाली ट्रेनों में तो सामान्य डिब्बे होते भी नहीं। रेलवे जब ऐसी श्रेणी की गाड़ियां चलाकर उनमें से आम व गरीब लोगों को बाहर कर देता है, तो अपने घाटे की भरपायी भी वह इन्हीं प्रीमियम क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों से क्यों नहीं करता?

रेलवे के नियम किस तरह से वंचित लोगों को अपमानित करते हैं, इसका एक उदाहरण यह भी है कि राजधानी, शताब्दी जैसी संभ्रांत किस्म की ट्रेनें काफी पीछे हों, तब भी सामान्य मेल-एक्सप्रेस को किसी स्टेशन पर रोककर इन गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है। क्या यह प्रवृत्ति गरीब यात्रियों को बेइज्जत नहीं करती? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, निचले तबके के लोगों को यूं जलील करना दिल को कचोटता है। ऐसे यात्रियों के साथ कम से कम मानवीय व्यवहार तो किया जाए। लिहाजा, सरकार और रेलवे को चाहिए कि किराया बढ़ाने की जगह लोगों को पहले ट्रेनों में सीटें उपलब्ध कराने की पहल करे। अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ट्रेनों में सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश में आज भी विपन्न तबके के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिनकी यात्रा सुगमता से होनी चाहिए।

अमन कुमार, टिप्पणीकार

मतदाता से धोखाधड़ी मतदान के सांविधानिक अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। -लिन वेस्टमोरलैंड

ठाकरे बंधुओं का हिंदी थोपने के नाम पर मराठी अस्मिता का राग अलापना और इसके लिए गुंडागर्दी तक को जायज ठहराना, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से पाने की कोशिश ही अधिक प्रतीत होती है। सभी भाषाओं का अपना सौंदर्य है। स्वार्थ के लिए भाषा को हथियार बनाना खतरनाक है।

भाषा की राजनीति

करीब दो दशकों बाद उद्धव और राज ठाकरे, दोनों का एक मंच पर आना और मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदी विरोध का झंडा बुलंद करना अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा तो प्रतीत होता ही है, यह कदम उनकी प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठाता है, जो हमेशा से ही संदिग्ध रही हैं। उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में महाराष्ट्र और गुजरात के विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की राजनीति समय-समय पर उभरती रही है। फिलहाल ठाकरे बंधुओं ने केंद्र की शिक्षा नीति को निशाना बनाया, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि उनकी रैली से पहले ही सरकार ने तीन भाषा नीति से जुड़े अपने आदेश वापस ले लिए, फिर भी रैली का आयोजन किया गया, तो इसकी वजह राजनीतिक ही है। कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी हिंदी थोपने के आरोप के बहाने स्थानीय भाषा बोलने वालों की भावनाएं भड़काने की रणनीति नई नहीं है। यह एक तरह का राजनीतिक अवसरवाद है, जिसका इस्तेमाल वोटों की खातिर होता रहा है। जब राजनीतिक दलों और नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में हो, तो यह रणनीति ही एकमात्र राह बचती है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से गुंडागर्दी को जायज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उन्होंने भाषा को ही राजनीतिक हथियार बना लिया है। जब वह मुंबई व महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने की बात करते हैं, तो यह बयान उनकी मंशा को और स्पष्टता के साथ उजागर करता है। दरअसल, अपनी सुविधा के लिए कभी उनका कांग्रेस के साथ खड़ा होना, तो कभी हिंदुत्व के मान बिंदु बन जाना उनकी राजनीति का तरीका है, जिसका भाषा व संस्कृति से कुछ लेना-देना नहीं है। हिंदी को थोपा गया बताकर ठाकरे बंधु जिस तरह का विमर्श खड़ा कर रहे हैं, वह भ्रामक होने के साथ राष्ट्रीय

एकता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हिंदी निस्संदेह भारत की संपर्क भाषा है, जिसे अधिसंख्य जनता समझती है। हिंदी की ऐसी स्वाभाविक स्वीकार्यता के बावजूद उसे खतरे के रूप में पेश करना तर्कसंगत नहीं दिखता। इतिहास गवाह है कि संकीर्ण क्षेत्रीयता और भाषाई उन्माद लंबे समय तक नहीं टिकता। महाराष्ट्र की जनता समझदार है और उसकी नजर इस पर भी होगी कि इन नेताओं को आखिर क्यों मराठवाड़ा में किसानों की दुर्दशा नहीं दिखती। जनता को चाहिए कि वह ऐसी विभाजनकारी राजनीति को नकारे, क्योंकि भाषा जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, न कि समाज को तोड़ने का औजार। भाषाएं सभी अच्छी हैं। अपने स्वार्थ के लिए इस विषय को राजनीतिक बनाने से स्थितियां खतरनाक मोड़ ले सकती हैं।

मतदाता सूची का कठोर सत्यापन जरूरी है

मतदाता सूची को दुरुस्त रखना चुनाव आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है। मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम कटने पर अदालत में चुनौती देने का कानूनी अधिकार तो है, पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका सांविधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के सत्यापन और पुनरीक्षण पर मचे सियासी बवाल की धमक अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग के 24 जून के आदेश को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए उसे रद्द करने के लिए याचिका दायर हुई है। ममता बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से भी ज्यादा खतरनाक बताते हुए आरोप लगाया है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव इस अभियान का असली लक्ष्य है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद-326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन पंजीकरण नियमावली, 1960 के नियमों के अनुरूप हो रही है। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक खातों और लॉकर्स का नियमित केवाईसी, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए मोबाइल नंबरों का सत्यापन, अपराध रोकने के लिए किरायेदारों की जांच और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटालों को रोकने के लिए डुप्लीकेट राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई का कोई विरोध नहीं होता। महाराष्ट्र में 40 लाख मतदाता बढ़ने पर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बिहार के बाद सभी राज्यों में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को ठीक करने का फैसला लिया है। इसलिए संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर मतदाता सूची शुद्धिकरण का विशेष अभियान सभी राज्यों में सफलतापूर्वक चले, तो 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले पूरे देश में मतदाता सूची दुरुस्त हो जाएगी।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

आजादी के बाद मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अब तक नौ बार हो चुका है और आखिरी बार विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार, 22 साल पहले पुनरीक्षण की प्रक्रिया एक महीने में पूरी हुई थी। याचिका के अनुसार, करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं, लेकिन 7.89 करोड़ में से लगभग 4.96 करोड़ का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें गणना फॉर्म के साथ

सिर्फ 2003 की मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण बीएलओ को देना होगा। बकाया तीन करोड़ मतदाताओं में, जिनके माता-पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है, उनके लिए भी आसान प्रक्रिया है।

उसके बाद बचे मतदाताओं को गणना फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं देना है, लेकिन 11 मान्य दस्तावेजों में से एक कागज देना होगा। इनमें सरकारी नौकरी या पेंशन, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, निवास, वन अधिकार, जाति, पारिवारिक रजिस्टर, भूमि या मकान के स्वामित्व आदि के प्रमाण पत्र और दस्तावेज शामिल हैं।

समस्या की असली जड़ को समझने के लिए साल-2022 में हुए जातीय सर्वे के साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और भारत मानव विकास सर्वे की रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों को समझना जरूरी है। उनके अनुसार जन्म प्रमाण पत्र 2.8 फीसदी, पासपोर्ट 2.4 फीसदी, मैट्रिक प्रमाण पत्र 45 फीसदी, जाति प्रमाण पत्र 16 फीसदी और सरकारी नौकरी के प्रमाण पत्र सिर्फ 1.57 फीसदी लोगों के पास हैं। जन्म-प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए साल-1969 में संसद ने कानून बनाया था, लेकिन बिहार में सिर्फ एक-चौथाई बच्चों का ही जन्म के बाद पंजीकरण हो रहा है। 2011 के सामाजिक-आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के 1.78 करोड़ परिवारों में से 65.58 फीसदी लोगों के पास भू-स्वामित्व नहीं है।

इसलिए 11 दस्तावेजों को साक्ष्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता देने की मांग हो रही है। लेकिन दस्तावेजों में हो रहे फर्जीवाड़े की वजह से उन्हें नागरिकता की विधिक मान्यता मिलना मुश्किल है। इसकी वजह से मतदाताओं को समस्या झेलने के साथ चुनाव आयोग को भी अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेजों की कमी की वजह से आधार या राशन कार्ड को मान्यता देना संविधान के साथ छल और लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। खाद्य मंत्रालय की नवंबर, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 80 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 5.8 करोड़ के राशन कार्ड को फर्जीवाड़े की वजह से रद्द किया गया था।

जन्मतिथि या जन्मस्थान के सत्यापन के बगैर जारी आधार कार्ड नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का विरोध हो रहा है, तो फिर आधार कार्ड को नागरिकता के दस्तावेज के तौर पर शामिल करने की मांग तर्कसंगत नहीं है। गौरतलब है कि संविधान के अनुसार, मतदाता सूची में नाम भारतीय नागरिकता का सबूत है, इस नाते इसकी कठोर पड़ताल जरूरी है।

जिन मतदाताओं का नाम निर्वाचन के बाद भी मतदाता सूची में शामिल है, उनका नाम मतदाता सूची से हटना ही चाहिए। जो लोग बिहार से बाहर निवास करते हैं और उनका नाम दूसरे राज्य की मतदाता सूची में शामिल है, उनका नाम भी बिहार की मतदाता सूची से हटना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया में विदेशी लोगों की पहचान होने से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। सत्यापन की इस प्रक्रिया में पार्टियों से जुड़े 1.56 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी शामिल रहेंगे। नियमों के तहत प्रत्येक बीएलए रोजाना मतदाता सत्यापन के 50 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अगर सभी पार्टियों से जुड़े बीएलए लोकतंत्र के शुद्धिकरण के इस प्रयास में सहयोग करें, तो रोजाना 75 लाख आवेदन जमा होने पर यह प्रक्रिया 11 दिन में पूरी हो सकती है।

मतदाता सूची को दुरुस्त रखना चुनाव आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है। संदिग्ध लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर करने से पहले अधिकारियों को सुनवाई के बाद तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा। मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम कटने वाले पीड़ित व्यक्ति को अदालत में चुनौती देने का कानूनी अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के खिलाफ सिर्फ आशंकाओं के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका सांविधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। संविधान में नागरिकता देने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए मतदाता सूची के सत्यापन में शिथिलता की मांग पर जोर देने से लोकतंत्र के साथ सांविधानिक व्यवस्था कमजोर होने के खतरे हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सायन देसी

लगन से जुटे रहकर आप ज्यादा आत्म-अनुशासित बनते हैं। आप अपने भीतर सफलता का लौह गुण विकसित करते हैं, जो आपको आगे किसी भी बाधा के पार ले जाएगा।

आत्म-अनुशासन और लगन सबसे बड़ी संपत्ति

जीवन में सफलता के लिए आत्म-अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह चरित्र की शक्ति और इच्छाशक्ति पर आधारित योग्यता है, यानी वह करने की योग्यता, जो आपको करना चाहिए, चाहे आपका इसे करने का मन हो या न हो। संकल्प लेते वक्त जो उत्साह रहता है, उसके चले जाने के बाद भी उस संकल्प पर काम करने की योग्यता को चरित्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या सीखते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण है कि आप अपना लक्ष्य हासिल करने तक कीमत चुकाने के लिए खुद को समर्पित और अनुशासित कर पाते हैं या नहीं। जीवन की हर अवस्था में आत्म-अनुशासन की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले तो अपने लक्ष्य तय करने में आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है।

लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाने के लिए आपको आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है। आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाओं को बदलने के लिए भी आत्म-अनुशासन की जरूरत पड़ती है। हर दिन योजना बनाने, अपने समय के उपयोग की प्राथमिकताएं तय करने और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। इसके अलावा, आपको हर दिन स्वयं में निवेश करने के लिए, खुद को पेशेवर तथा व्यक्तिगत रूप से विकसित करने और आवश्यक चीजें सीखने के लिए आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है, ताकि आप वे लक्ष्य हासिल कर सकें, जो आपके लिए संभव हैं। यही नहीं, अपने धन को बचाने व निवेश करने के लिए भी आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है, ताकि आप अपने कामकाजी जीवनकाल में ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। अपने लक्ष्यों और सपनों पर टिके रहने के लिए आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है। अपने विचारों को अपनी शंकाओं और डरों से दूर रखने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। विफलताओं और समस्याओं की स्थिति में निराश होने के बजाय सकारात्मक व सृजनात्मक बने रहने के लिए भी आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है। शायद आत्म-अनुशासन का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब लगन से जुटे रहना है, जब यात्रा मुश्किल हो। लगन सक्रिय आत्म-अनुशासन है। जब आप विपत्ति और निराशा के सामने लगन से जुटे रहते हैं, तो आप हर बार लगन की आदत का निर्माण करते हैं। आप अपने चरित्र और व्यक्तित्व में गर्व, शक्ति और आत्म-गौरव का निर्माण करते हैं। आप ज्यादा शक्तिशाली और संकल्पवान बनते हैं। लगन से जुटे रहकर आप ज्यादा आत्म-अनुशासित बनते हैं। आप अपने भीतर सफलता का वह लौह गुण विकसित करते हैं, जो आपको आगे किसी भी बाधा के पार ले जाएगा, जो आपके जीवन में आएगी। पूरे इतिहास में स्त्री-पुरुषों की महान उपलब्धियां लगन की विजय की कहानियां हैं। सभी महान लोगों की सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले मुश्किलों और विपत्तियों को झेलना पड़ा है। चरित्र की शक्ति उनके अटल संकल्प से प्रकट हुई, जिसने उन्हें महान बनाया। आत्म-अनुशासन और लगन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। (जे एलमपुएल: द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लीन के अनुदित अंश)

स्वयं पर निवेश करें

एक ही जीवन है, इसलिए आत्म-अनुशासन के साथ हर दिन स्वयं में निवेश करें। आप अपने भीतर वह गुण विकसित करें, जिससे किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकें। सभी कठिनाइयों से लड़ने के लिए आत्म-अनुशासन की आवश्यकता होती है। डीमैट अकाउंट से ज्यादा बेहतर है, स्वयं पर निवेश करें और पहले से स्वयं को बेहतर बनाएं।

सूत्र

दूसरा पहलू

बजानी न आती हो, तो बांसुरी बेचना संभव नहीं। कभी स्कूल न जा पाए मंजूर अली ने सबसे पहले बांसुरी से दोस्ती की।

अपनी धुन के साथ सुंदर दिखते हैं मंजूर अली

जिस भी दिशा से आते हैं मंजूर अली, अपने साथ ले आते हैं बांसुरी के ढेर सारे सुर। वह सड़क किनारे किसी पुलिया की टेक लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर बांसुरी में लगाते हैं फूंक। उंगलियां छेदों को खोलने और बंद करने में हो जाती हैं व्यस्त। हवा में तैरने लगती है कोई फिल्मी धुन। कुछ लोग देखकर भी निकल जाते हैं सरपट, लेकिन कुछ लोगों को दुनिया के खरे अवाध-शनाप शोर के बीच अपनी ओर खींच लेती है धुन। वे भूल जाते हैं, क्या खरीदने आए थे। वे पूछने लगते हैं बांसुरी के दाम। मंजूर उत्साह से बताते हैं- 'यह मुरली पचास रुपये की है, यह सौ रुपये की और यह 1,500 रुपये की।' छोटी है तो मुरली, बड़ी है तो बांसुरी। साथ भले ही मुरली और बांसुरी में बहुत फर्क न करता हो, पर व्यवहार में ज्यादा छेद वाली बांसुरी कहलाती है और कम छेद वाली मुरली, जिसे सीधे फूंक मारकर बजाया जा सकता है। कुछ देर उसकी धुन सुनने के बाद रहमान खरीदने या किसी काम से निकले हर आदमी की जेब में होती है एक छोटी-सी बांसुरी। मंजूर अली की मांग बढ़ जाती है। तीन हजार रुपये तक की बांसुरी बेचने वाले मंजूर अयोध्या से सटे खेड़ाबल्ल के रहने वाले हैं और नोएडा में किराये के एक छोटे-से कमरे में रहते हैं। हर सुबह लगभग 10 बजे वह घर से निकल पड़ते हैं। किसी दिन नोएडा का कोई रिहाइशी इलाका, तो कभी गाजियाबाद का कोई मुहल्ला। रविवार का दिन गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के नाम दर्ज है। वही होता है हर रविवार।

देव प्रकाश चौधरी

कुछ देर मंजूर की धुन को ध्यान से सुनने के बाद हर आदमी की जेब में होती है एक छोटी-सी बांसुरी। मंजूर अली की मांग बढ़ जाती है।

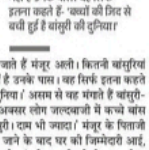

फिलहाल बांसुरियां बिक जाती हैं? इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं है उनके पास। वह सिर्फ इतना कहते हैं- 'बच्चों की जिद से बची हुई है बांसुरी की दुनिया।'

किसी भी दिशा से कोई धुन लेकर हाजिर हो जाते हैं मंजूर अली। कितनी बांसुरियां बिक जाती हैं? इसका कोई सटीक जवाब नहीं है उनके पास। वह सिर्फ इतना कहते हैं- 'बच्चों की जिद से बची हुई है बांसुरी की दुनिया।' असम से वह मंगाते हैं बांसुरी- 'आसपास बनने वाली बांसुरियों में दम नहीं। अक्सर लोग जल्दबाजी में कच्चे बांस से बना देते हैं बांसुरी और वह हो जाती है बेसुरी। दाम भी ज्यादा।' मंजूर के पिताजी भी करते थे यही काम। उनके अचानक गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी आई, तो कभी स्कूल न जा पाए मंजूर ने सबसे पहले बांसुरी बजानी सीखी। बजानी न आती हो, तो इसे बेचना संभव नहीं। 38 साल के मंजूर पिछले 21 साल से बांसुरी के सहारे अपने और अपने परिवार के लिए जुटा रहे हैं खुशियां। अपने काम से खुश मंजूर बिना नागा हर सुबह निकल पड़ते हैं काम पर। काम पर निकले लोग दुनिया के सुंदर लोग होते हैं। मंजूर अली भी अपनी 'धुन' के साथ सुंदर दिखते हैं।

आंकड़े

ट्रेन से यात्रा

स्टेटिस्टा सर्वे के अनुसार, भारतीय लंबी दूरी की यात्रा सबसे ज्यादा ट्रेन से करते हैं। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है।

आंकड़े लंबी दूरी की रेल टिकट खरीदने वालों के। स्रोत : statista

एक किसान अकाल पड़ने के बाद भी कुछ अनाज पक्षियों को देता। अंत में भगवान ने स्वप्न में उसे सूर्योदय से पहले खेत में जाने को कहा और फिर चमत्कार हुआ।

भक्ति और दान

एक छोटे-से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा पक्षियों के लिए छोड़ देता। उसका मानना था कि दान और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। वह हर सुबह भगवान विष्णु की पूजा करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन रामू का विश्वास डगमगाया नहीं। वह इस भयंकर अकाल के बाद भी हर दिन थोड़ा-सा अनाज पक्षियों के लिए रख देता। गांव वाले इसे देखकर हैरान होते। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करता, 'हे प्रभु, मेरे गांव को इस संकट से बचाओ।'

एक रात, स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, 'रामू, तुम्हारी भक्ति और दान ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सूर्योदय से पहले अपने खेत में जाना, वहां तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा।' रामू सुबह, सूर्योदय से पहले खेत पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके सूखे खेत में एक छोटा-सा जलस्रोत फूट रहा था। उसने उस जल से अपने खेत को सींचा, और कुछ ही दिनों में उसके खेत लहलहाने लगे। गांव वाले हैरान थे कि सूखे में रामू के खेत में इतनी हरियाली कैसे आई। रामू ने सबको बताया कि यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। उस जलस्रोत से धीरे-धीरे गांव फिर से हरा-भरा हो गया। उसकी भक्ति और दान की भावना ने पूरे गांव के लिए चमत्कार कर दिखाया।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 07 जुलाई, 1951

कोरिया में युद्ध बंद हुआ तो उसका श्रेय सेना को

यूरोप की संयुक्त सेनाओं के सुप्रीम कमांडर जनरल आईजन हावर ने कहा कि कोरिया में युद्ध बंद हुआ, तो उसका श्रेय हमारी सैन्य शक्ति को जाएगा। हमने कम्युनिस्टों की आक्रमणकारी नीति को आगे नहीं बढ़ने दिया।

क्या भावी चुनौतियों के लिए तैयार है ब्रिक्स

शी जिनपिंग और पुतिन की अनुपस्थिति भारत के लिए अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ एजेंडे को आगे बढ़ाकर नेतृत्व करे।

रहीस सिंह — **मुद्दा**

पांच देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंच चुके हैं, जहां रियो डि जेनेरियो में हो रहे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वह हिस्सेदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस बहुपक्षीयता को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, जो वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है।

इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत का झुकाव बहुपक्षीयता की तरफ है और ब्रिक्स इसके लिए बेहतर मंच हो सकता है। लेकिन क्या यह वाशिंगटन और उसके यूरोपीय गठबंधन से मुकाबला करने में समर्थ है? 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' इस मंच की उपलब्धि है, पर व्यवहारिक दृष्टि से चीन इसका उपयोग अपनी 'सॉफ्ट पावर' के रूप में करता दिख रहा है।

चीनी सेना द्वारा 'डोकलाम' और 'गलवान' में जो कुछ किया गया, उसके बाद से भारत और चीन के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि ब्रिक्स उसे पाट नहीं सकता। दोनों देशों की दूरी को एक झलक किंगदाओ (चीन) में

एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में दिखी, जहां संयुक्त बयान में पाकिस्तान में हुई आतंकवादी घटना को तो जगह दी गई, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को नहीं। अगर पहलगाम हमले को इसमें जगह दी जाती, तो चीन का सदाबहार मित्र (पाकिस्तान) कठघरे में खड़ा हो जाता। इसलिए भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। चीन और रूस की मित्रता ब्रिक्स से यूरोप और अमेरिका की दूरी बढ़ा देती है। यही नहीं बीजिंग-मास्को-तेहरान के बीच संबंध अमेरिका को अखर रहा है। ऐसे में ब्रिक्स वैश्विक व्यवस्था के साथ या समानांतर लंबी दूरी तक चल पाएगा, कहना मुश्किल है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डि सिल्वा भले ही ब्राजील को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल करने के पक्षधर न हों, लेकिन शी जिनपिंग से उनके बेहतर संबंध हैं। शेष सदस्य देशों में- दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इंडोनेशिया आदि चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हैं। इससे ब्रिक्स की निष्पक्ष और बहुपक्षीय संबंधों की नैतिकता का आकलन किया जा सकता है। ये देश चीनी एलायंस का हिस्सा पहले हैं, ब्रिक्स का बाद में। यही कारण है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स से जुड़ने से इन्कार कर दिया। वैसे भी गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों ने जिस तरह से ब्रिक्स की परिकल्पना की थी और इसको लेकर जो उम्मीदें जताई थीं, वे अब नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि यह बहुपक्षीय-संयोजन का दौर है और भारत इसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें टकराती हुई दिख रही हैं। जैसे भारत एक तरफ शंघाई सहयोग संगठन में चीन के साथ है, जिसे अमेरिका और नाटो देश प्रतिद्वंद्वी संगठन के तौर पर देख रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत हिंद-प्रशांत में अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल है, जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। इससे यह भी पता चलता है कि सदस्य देशों के बीच एकता कितनी कमजोर है।

ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लेकर चलने के साथ ही वैश्विक आबादी में लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक जीडीपी में करीब 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में लगभग 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। हाल के दशकों में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की साख जी-7 देशों के मुकाबले मजबूत हुई है। ब्रिक्स देश, आर्थिक व सामरिक दृष्टि से पर्याप्त क्षमता रखते हैं और भू-राजनीतिक संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट हो रहा है। इनके पास बड़ा मध्य-वर्ग तथा बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन परिणाम वे नहीं दिख रहे, जो 'ड्रीमिंग विद ब्रिक्स : द पाथ टू 2050' में अनुमान के आधार पर खोजे गए थे।

जाहिर है, ब्रिक्स अभी अपने उन लक्ष्यों से बहुत दूर खड़ा है, जो इसकी स्थापना और उसके बाद पिछले 16 शिखर सम्मेलनों में एक-एक करके तय किए गए। रियो ब्रिक्स का आदर्श वाक्य है- 'अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत बनाना।' लेकिन इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह अवसर है कि वह इसका फायदा उठाकर ग्लोबल साउथ की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के एजेंडे को प्रमुखता से आगे बढ़ाकर अपना नेतृत्व सिद्ध करे।

बहरहाल सैद्धांतिक दृष्टि से तो ब्रिक्स देश अब 'इकनॉमिक ब्लॉक फॉर ऐन इनोवेटिव फ्यूचर' से आगे निकलकर 'ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड रिसचोर्टिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ' की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन दुनिया में जिस प्रकार के जियो-स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर स्थायी रूप से पड़ने वाला है, उसके लिए ब्रिक्स कितना तैयार है, यह अस्पष्ट है। ऐसे में भावी चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। लेकिन क्या ब्रिक्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार है?

दैनिक जागरण
किसी भी कार्य का आरंभिक पड़ाव सबसे कठिन होता है

सरकारी बंगले

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को धन्यवाद कि उसने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ की ओर से सरकारी बंगला न खाली करने पर केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि उनसे बंगला खाली कराया जाए। यह अभूतपूर्व है। दिल्ली अथवा देश के अन्य हिस्सों में सरकारी बंगलों में किसी को भी तय अवधि से ज्यादा रहने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है और अक्सीर में होता भी रहा है। यह ठीक है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आठ माह बाद भी सरकारी बंगला खाली न कर पाने के कुछ कारण गिनाए हैं और इन कारणों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि उन्हें नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वे अपने फैसलों और फैसलों से इतर संबोधनों के जरिये नैतिक आचरण पर बल देते रहे हैं। सरकारी बंगला विवाद से उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। यह सही है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी बंगले में रहने के लिए तय किराया दे रहे हैं, लेकिन यह किराया कुल मिलाकर मामूली ही होता है और जिस इलाके में वे रह रहे हैं वह तो अति विशिष्ट क्षेत्र है।

यह पहली बार नहीं है जब सरकारी बंगले को लेकर कोई विवाद उठा हो। इस तरह के विवाद पहले भी उठते रहे हैं। ऐसे सांसदों, पूर्व मंत्रियों की गिनती करना कठिन है जिन्होंने सांसद अथवा मंत्री न रहने के बाद सरकारी बंगला छोड़ने में आनाकानी की। कुछ नेताओं से तो जबरन बंगला खाली कराना पड़ा। यह भी एक तथ्य है कि कुछ नेता एवं पूर्व अधिकारी अथवा कथित विशिष्ट व्यक्ति सरकार की कृपा से लंबे समय तक सरकारी बंगलों में काबिज रहे। कुछ लोगों की ओर से यह भी कोशिश की गई कि उनके नेता की स्मृति संजोने के नाम पर उन्हें अथवा उनके स्वजनों को सरकारी बंगला सदैव के लिए आवंटित कर दिया जाए। दुर्भाग्य से ऐसे कुछ नेता अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए। ऐसा इसीलिए होता रहा, क्योंकि सरकारी बंगलों में किसे रहना चाहिए और किसे नहीं, इसके लिए जो नियम-कानून बने हुए हैं वे कुल मिलाकर कागजी ही अधिक हैं। इन नियमों पर सही तरीके से पालन मुश्किल से ही होता है। दिल्ली में केंद्र सरकार के बंगलों में अयाचित लोगों के रहने के किस्से तो चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन राज्यों के ऐसे किस्से दबे-छिपे ही अधिक रहते हैं। सच तो यह है कि कई राज्यों की राजधानियों में न जाने कितने अयाचित लोग सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। सरकारी बंगले राष्ट्र की संपत्ति हैं। किसी भी सरकार को इन्हें किसी को मनमाने तरीके से आवंटित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अक्सीर में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में सरकारों को आदेश-निर्देश दिए हैं, लेकिन उन पर पालन शायद ही हो रहा होगा।

अपराध नियंत्रण की चुनौती

बिहार की राजधानी पटना के अति पाश क्षेत्र में एक उद्योगपति गोपाल खेमका की शुक्रवार देर रात हत्या के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। एक अपराधी का यह दुस्साहस ही है कि वह कार पर बैठे व्यक्ति को गोली मारता है और आराम से निकल जाता है, जबकि उस क्षेत्र में कई अति विशिष्ट लोगों के आवास ही नहीं, पास ही में थाना भी है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि पुलिस गश्त और अपराध नियंत्रण के तमाम दावों के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कमी कहां है, जब सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आमजन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पुलिस तंत्र है, परंतु हाल के दिनों में कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें स्वयं कतिपय पुलिसकर्मी ही उन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिन पर उसे रोकने और कार्रवाई का दायित्व था। हालांकि, ऐसे मामलों में शासन ने उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की। यह जरूरी भी है। लेकिन पटना के पाश इलाके में जिस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे हर थाना क्षेत्र की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और वैसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जहां कार्रवाई की गति बहुत ही धीमी है और शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं। घटनाएं होती रहती हैं, पर यह महत्वपूर्ण है कि उससे सीख लेते हुए क्या रणनीति बनाई गई। हाल ही में पटना में दिनदहाड़े फायरिंग की गई। उसी समय एडीजी विधि व्यवस्था भी जा रहे थे और उन्होंने उसका पीछा किया, परंतु थाना को पुलिस का पता नहीं था। इसे दुरुस्त करना होगा, ताकि अपराध पर लगाम लग सके और अपराधियों में दहशत हो, यह सबसे बड़ी चुनौती है।

> अपराध पर लगाम के लिए अपराधियों में दहशत सबसे बड़ी चुनौती है

विकराल होता जलवायु परिवर्तन का संकट

शिवकांत शर्मा

तापमान में बढ़ोतरी बादलों में पानी की मात्रा बढ़ा देती है और उनके फटने की आशंका बढ़ जाती है। बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है

जून के दौरान इस साल इंग्लैंड और स्पेन में रिकार्ड गर्मी पड़ी। लंदन में तापमान 35 डिग्री था, जबकि स्पेन के दक्षिणी शहर कोर्दोबा में 41 डिग्री। स्पेन और पुर्तगाल के अन्य कई शहरों में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इटली, ग्रीस, फ्रांस और नीदरलैंड्स में भी भीषण गर्मी पड़ी। इस गर्मी से आठ लोगों की मौत हो गई और तुर्किये में दावानल से बचाने के लिए 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। यूरोप में गर्मी का मौसम जून से लेकर जुलाई और अगस्त तक रहता है। जून में मौसम वैसा रहता है जैसा उत्तर भारत में सामान्य तौर पर अप्रैल के दौरान रहता है। हालांकि इस बार दिल्ली में भी अप्रैल का महीना रिकार्ड गर्मी का रहा। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलनों में 70 से अधिक लोग मारे गए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा।

जलवायु विज्ञानियों का कहना है कि यूरोप में धरती से उठती गर्मी को वायुमंडल पर बने उच्च दाब ने गुंबद की तरह घेर लिया था जिसे हीट डोम कहते हैं। जून की ग्रीष्म लहर उसी का परिणाम थी। इसी तरह के हीट डोम दो वर्ष पहले पश्चिमी अमेरिका, चीन और दक्षिणी स्पेन पर बने थे। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पारा 53.9 डिग्री और स्पेन में 46 डिग्री जा पहुंचा था। हीट डोम बनने और बादल फटने की घटनाएं वायुमंडल में गर्मी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जा रही हैं। धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.36 डिग्री बढ़ चुका है। इसे 1.5 डिग्री से आगे बढ़ने से रोकने के लिए पेरिस की जलवायु संधि हुई थी। तापमान में हुई वृद्धि के एक चौथाई का जिम्मेदार अकेला अमेरिका है। फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस संधि से हाथ खींच लिया था। विज्ञानियों की आशंका है कि चीन समेत बाकी देश जिस गति से अपना गैस उत्सर्जन घटा रहे हैं उससे धरती का तापमान 1.5 डिग्री पर नहीं रुक पाएगा। वह 2.7 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसके भयावह परिणाम होंगे।

नेचर पत्रिका के अनुसार तापमान वृद्धि को यदि 1.5 डिग्री तक न रोका गया तो इसकी सबसे बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है। भारत के करीब 60 करोड़ लोग भीषण गर्मी से प्रभावित होंगे। गर्मी बढ़ने से मिट्टी तेजी से सूखेगी जिसे नम रखने के लिए बड़ी मात्रा में भूजल निकालना होगा और उसके स्रोत सूखने लगेंगे। भारत दुनिया में गेहूं और धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भूजल सूखने से उनकी उपज पर असर पड़ेगा। बागवानी, पशुपालन और

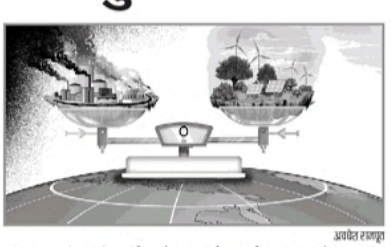

प्रतीकात्मक छायाचित्र

मत्स्यपालन भी प्रभावित होंगे। औसत तापमान में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी बादलों में सात प्रतिशत अधिक पानी भर सकती है। अधिक पानी से लदे बादलों के फटने की आशंका बढ़ जाती है। बादल फटने से भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। भारत में हर साल दो से तीन हजार लोग बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मारे जाते हैं। तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियरों पर भी बर्फ की जगह पानी बरसने लगा है जिसकी वजह से वे तेजी से पिघल कर छीज रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर ही 15-20 मीटर प्रति वर्ष की गति से छीज रहा है और पिछले तीस वर्षों में लगभग 700 मीटर छीज चुका है। कुछ अन्य ग्लेशियरों की हालत और भी चिंताजनक है। कई ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से झीलें बन गई हैं, जिनके टूटने से बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। गत मई में स्विट्जरलैंड का बर्च ग्लेशियर टूटने से उसकी तलहटी में बसा गांव ब्लाटन उसके मलबे में दब गया था। ग्लेशियरों के पिघलने से भूस्खलन हो रहे हैं और इनके सूखने पर गंगा जैसी सदानीरा नदियों भी बरसाती में बदल सकती हैं और जलसंकट पैदा हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन की विभीषिका की रोकथाम के लिए जो वैश्विक सहमति बनी थी वह पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुई है। पहले तो कोविड महामारी ने आर्थिक संकट खड़ा किया। उसके बाद यूक्रेन पर रूस के हमले से ऊर्जा और अनाज के दामों में आग लगी और महंगाई बढ़ी। इससे लोगों और सरकारों दोनों के बजट बिगड़ गए। रही-सही कसर ट्रंप ने पेरिस संधि से हाथ खींचकर, व्यापार जंग छेड़कर और विश्व व्यवस्था को अस्थिर बनाकर पूरी कर दी। जो अमेरिका लोकतांत्रिक देशों को चीन और रूस की तानाशाही के जोखिम से बचाता था, उसे ट्रंप ने जोखिम में बदल दिया। अमेरिका पर भरोसा करने वाले देशों को उम्मीद थी कि उसकी सुरक्षा के स्थ में वे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने संसाधन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और नए बाजार खोजने में लगाने पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की तेज होती तपिश के बीच ही सरकारों को अपने बजट उस रक्षा सामग्री पर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके निर्माण और प्रयोग से जलवायु परिवर्तन की गति और तेज होगी।

एक तिहाई ग्रीनहाउस गैस छोड़ने वाला चीन स्वच्छ ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा विकास के काम में लगा है। साइकिलों का देश अब बिजली की कारों, बैटरियों, स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की तकनीकों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता बन चुका है। भारत को भी अब हाइड्रोजन, सौर, पन-पवन और परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि समूचे उत्तर भारत पर फैले जहरीली हवा और धूल के बादल छंट सकें। भारत में हर साल 16 लाख लोग वायु प्रदूषण से और छह लाख जल प्रदूषण से मरते हैं जो दुनिया में वायु प्रदूषण से मरने वालों का एक चौथाई और जल प्रदूषण से मरने वालों का आधा है। इसलिए 180 देशों की पर्यावरण प्रदर्शन तालिका में भारत 176वें स्थान पर है। यही हाल रहा तो भारत की जीडीपी का 6.4 से 10 प्रतिशत प्रदूषण की भेंट चढ़ने लगेगा। दो साल पहले हुए सर्वेक्षणों के अनुसार भारत के 85 प्रतिशत लोग जलवायु परिवर्तन से चिंतित हैं और 87 प्रतिशत चाहते हैं कि उसकी रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए। हमें यह भी समझना होगा जलवायु परिवर्तन कोई ऐसी जंग नहीं जिसे देश की सीमा पर सेना भेजकर जीत लिया जाए, बल्कि ऐसी जंग है जिसमें दुश्मन हमारे ही भीतर बैठा है जिसे निजी व्यवहार को बदले बिना नहीं जीता जा सकता।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

नए आपराधिक कानूनों की स्वीकार्यता

सुशील कुमार गुप्ता

अश्विता गुप्ता

नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बना रहे हैं

एक जुलाई, 2024 को भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को तीन आधुनिक विधियों-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) से बदल दिया। इन सुधारों का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सम्मिलित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण करना था। लागू होने के पहले दो महीनों में ही इन नए प्रविधानों के तहत 5.56 लाख से अधिक एफआइआर दर्ज हुईं, जो इनकी सक्रिय स्वीकार्यता को दर्शाती हैं। इसके साथ ही 5.6 लाख से अधिक पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जो प्रशासन की तैयारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय न्याय संहिता ने संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ हत्या जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे यह वर्तमान समय की आपराधिक प्रकृति के अनुरूप बन गई है। इसमें कुछ अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है, जो दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक न्याय की ओर एक संवेदनशील कदम है। हालांकि कई प्रविधान अब भी आइपीसी से मिलते-जुलते हैं, लेकिन यह निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने का एक व्यावहारिक तरीका माना जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने प्रक्रिया संबंधी कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब नागरिक जीरो एफआइआर और ई-एफआइआर दर्ज कर सकते हैं और केस फाइलें और चार्जशीट डिजिटल रूप में तैयार की जा रही हैं। जांच अधिकारियों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे घटनास्थल से तुरंत साक्ष्य एकत्र कर सकें और अपलोड कर सकें। दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुलिस स्टेशनों में वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं जिससे रिमांड और गवाही की कार्यवाहियां दूरस्थ रूप से की जा सकें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्यों में से है। राज्य के सभी 75 जिलों में मोबाइल फारेंसिक वैन तैनात की गई हैं। 60 हजार नए भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ताकि नवीन व्यवस्था में प्रशिक्षित हो सकें।

बीएनएसएस के अंतर्गत मोबाइल फारेंसिक साइंस यूनिट्स का विस्तार एक प्रमुख सुधार है। इसके साथ ही फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जा रहा है, ताकि वे साइबर अपराध और डीएनए परीक्षण जैसे जटिल मामलों की जांच कर सकें। हालांकि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 32 पूर्ण रूप से कार्यशील एफएसएल थीं, लेकिन हालिया निवेश से स्थिति में सुधार की दिशा स्पष्ट है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल युग की मांगों के अनुरूप साक्ष्य कानून को अद्यतन करता है। अब ईमेल, मेटा डाटा, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डाटा और यहां तक कि ब्लाकचेन रिकार्ड को भी कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हैश वैल्यू और डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिए गए हैं। अदालतें अब ई-गवाही और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ साक्ष्य स्वीकार कर सकती हैं। विशेष रूप से 22 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा विकसित ई-साक्ष्य एप को अपनाया है, जिससे डिजिटल साक्ष्य को संग्रहित और प्रस्तुत करना सरल हो गया है। ये परिवर्तन ई-कोर्ट्स परियोजना की बुनियाद पर निर्मित हुए हैं, जिसके तहत 18,000 से अधिक अदालतों का डिजिटलीकरण किया गया है और आनलाइन फाइलिंग एवं वीडियो सुनवाई की व्यवस्था पहले से अस्तित्व में है।

हालांकि सुधारों की दिशा में ठोस प्रगति हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता बाधा बन रही हैं। फारेंसिक प्रयोगशालाएं सीमित हैं और अदालतों तथा पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की कमी भी गंभीर विषय है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2022 के बीच साइबर अपराधों में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उच्च तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दर्शाता है। इन सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नीति-निर्माण उपाय आवश्यक हैं। सामुदायिक सेवा को एक संस्थागत दंड व्यवस्था के रूप में लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए न्यायिक प्रशिक्षण और दिशानिर्देश तय किए जाएं। बीएनएसएस के अंतर्गत गवाह संरक्षण नियमों को राज्य स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें पहचान छिपाने, स्थानांतरण और वीडियो गवाही की सुरक्षित व्यवस्था हो। प्रत्येक जिले में फारेंसिक सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल और स्थायी, दोनों प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही एक राष्ट्रीय डिजिटल अनुपालन डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, जो एफआइआर, जांच की प्रगति और रिमांड की प्रक्रिया पर निगरानी रखे। अंततः विधिक साक्षरता अभियान चलाकर नागरिकों को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

नए आपराधिक कानून एक सकारात्मक और सुविचारित बदलाव के प्रतीक हैं। पहले वर्ष में एक मजबूत आधार स्थापित हो चुका है। अब आवश्यकता है इसे और मजबूती से आगे बढ़ाने की। यदि यह यात्रा प्रशिक्षण, निवेश और नीति समर्थन से सशक्त की जाए, तो भारत की न्याय प्रणाली वास्तव में अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बन सकती है।

(सुनील पूर्व आइपीएस अधिकारी और अश्विता दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि की छात्रा हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वामित्व-बोध

संसार हमारे जन्म लेने से पहले भी था और हमारे मरणोपरांत भी रहेगा। यही शाश्वत सत्य है, जिसे स्वीकार कर लेना आत्मबोध का प्रथम सोपान है। मनुष्य इस विस्तृत ब्रह्मांड का क्षणिक अतिथि मात्र है। एक ऐसा यात्री जो चिरकालिक रात्रि में दीपशिखा के समान कुछ क्षणों के लिए व्यक्त एवं आलोकित होता है और फिर उसी गहन अंधकार में विलीन हो जाता है। विडंबना यह है कि यह क्षणभंगुर अस्तित्व भी जब चेतना का रूप धारण करता है, तो स्वामित्व का मोहजाल उसमें अंकुरित हो उठता है। विधाता ने हमें साधनों के उपभोग का अधिकार दिया है, परंतु उनमें स्वामित्व का भाव पालने की अनुमति नहीं।

मनुष्य की विडंबना यह है कि वह अनुकूलताओं को 'सुख' और प्रतिकूलताओं को 'दुख' का नाम दे देता है। जैसे कोई बालक जल में अपनी परछाई को देखकर हर्षित होता हो और जब वह लहरों से विखंडित हो जाती है, तो वह रो पड़ता है। सुख और दुख दोनों उसी परछाई की भांति हैं-नश्वर, परिवर्तनशील और अध्रुव। बुद्ध कहते हैं, 'सब दुखों की जड़ तृष्णा है।' देखा जाए तो यह तृष्णा वस्तुओं की नहीं, स्वामित्व की है।

जब तक कोई वस्तु अप्राप्य थी, तभी तक उसका आकर्षण था। जैसे ही उस पर स्वामित्व मिला, उसका आकर्षण समाप्त हो गया। हमें समझना है कि पृथ्वी, नदियां, आकाश के संबंध और भोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं, सब 'क्षणिक सुख' के रूप में दिए गए हैं। जो सूर्य सूर्योदय के समय आशा का संचार करता है, वही सूर्यास्त के समय मन को बोझिल भाव से भर सकता है। जैसे ही हम अंतर्मन में जान लेते हैं कि ये सब स्थायी संपत्ति नहीं हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम स्वस्थ चित्तवृत्ति के साथ संसार को एक संगीत की भांति अनुभव करते हैं, जो सुनने के लिए है, थिरकने के लिए है, किंतु किसी बंधन में बांधने के लिए नहीं।

दिवंकल तोमर सिंह

बुजुर्गों को बोझ समझने की बढ़ती प्रवृत्ति

सोनम लववंशी

जिन बच्चों के लिए सबकुछ किया, आज वही बच्चे अपने बुजुर्गों को बोझ समझ रहे हैं

जिन चौखटों पर कभी मां-बाप की आहटें जीवन को सुकून देती थीं। जहां उनके साये में पीढ़ियां संवरती थीं, आज वही चौखटें बुजुर्गों के लिए अजनबी हो गई हैं। अपने ही घर के दरवाजों से अब उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। यह कोई भावुक या कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान का शर्मनाक यथार्थ है।

हाल ही में मुंबई में एक कैंसर पीड़ित 70 वर्षीय वृद्धा को उसके ही पोते ने 'आरे कालोनी' के जंगल में छोड़ दिया। पुलिस को वह महिला कचरे के ढेर पर पड़ी मिली, बदहवास, भूखी और अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। पुलिस ने 'माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम' के तहत आरोपी पोते को गिरफ्तार किया। यह अकेली घटना नहीं है जो हमें झकझोरती हो। पुणे में एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता को घर से बाहर निकाल दिया, पालघर में बेटों ने अपने ही बुजुर्ग माता-पिता को पीटकर संपत्ति हड़प ली। ये घटनाएं अब अपवाद नहीं रहीं।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश की जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा बुजुर्गों का है, और वर्ष 2050 तक यह अनुपात 17 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यानी हर छठा भारतीय बुजुर्ग होगा, पर क्या बुजुर्ग को सम्मान से जीने का हक मिलेगा? वृद्धाश्रम भरते जा रहे हैं, वहीं बेटों के घरों में खालीपन है। आधुनिकता के नाम पर यह कैसा आत्महीन समाज बन रहा है जो अनुभव, ममता और त्याग को बोझ मानने लगा है? यह केवल पारिवारिक रिश्तों की टूटन नहीं, हमारी सामूहिक चेतना की गिरावट है। जिस भारत को हम विकसित कहने लगे हैं, वहां तकनीक की रोशनी तो है, पर संवेदनाओं का अंधकार भी गहराता जा रहा है। अब हम एक ऐसे यंत्रवत समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां संवेदना केवल पाठ्यक्रमों और स्मारकों में मिलेगी।

बुजुर्गों की यह स्थिति अचानक नहीं हुई है। यह उस सांस्कृतिक पतन की परिणति है, जहां 'स्वतंत्रता' के नाम पर 'सामूहिक जिम्मेदारी' को तिलांजलि दे दी गई। पहले संयुक्त परिवार थे- अनेक दिल, एक घर। एकल परिवारों में कमरे हैं, अपनापन नहीं। स्मार्टफोन की रोशनी है, लेकिन मां की आंखों की झिलमिलाहट कहीं खो गई है। जो दादी कहानियां सुनाती थीं, वे अब एकांत में आंसू पोछ रही हैं। यह केवल बुजुर्गों की नहीं, हमारी सामाजिक चेतना की पराजय है।

समझना होगा कि 'विकास' केवल जीडीपी नहीं, मानवीय गरिमा में निहित है। हमें उन धूल भरी चौखटों की ओर फिर से लौटना होगा, जहां मां की थाली में सबसे बड़ा रोटी का टुकड़ा बापू के हिस्से आता था, और दादी की हंसी सबसे सस्ती दवा थी। अब समय आ गया है कि हम 'बड़ों के सम्मान' को फिर से जीवंत व्यवहार बनाएं। वरना एक दिन हमारे बच्चे भी हमें उसी जंगल में छोड़ आएंगे, जहां आज हम अपने माता-पिता को बेबस छोड़ते देख रहे हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

हिंदी विरोध की विकृत राजनीति

'भाषाई कट्टरवंधी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं द्वारा की जा रही निकृष्ट भाषाई राजनीति को स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ रेखांकित किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल सरकार, बल्कि अपनी मूल पार्टी गंवाकर हाशिए पर पहुंचे उद्धव ठाकरे अब अपने भाई राज ठाकरे से मिलकर मराठी अस्मिता की आड़ में हिंदी विरोध को सत्ता हासिल करने का जरिया बना रहे हैं। जहां उद्धव के पास अपनी एक पार्टी है, जिसका लोकसभा-विधानसभा में भी धीड़ा-बहुत प्रतिनिधित्व है, लेकिन राज तो राजनीतिक रूप से करीब-करीब अप्रासंगिक हैं। ठाकरे बंधुओं की इस कुत्सित भाषाई राजनीति से सावधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस बहुत संभलकर चल रहे हैं। मराठी अस्मिता के पक्षधर होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र के भीतर भारत की एक प्रमुख संपर्क भाषा हिंदी का विरोध स्वीकार नहीं। भारत के किसी भी राज्य में हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं का विरोध होना भी नहीं चाहिए। सभी राज्य अपनी मातृभाषा की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए अन्य भाषाओं का सम्मान करने में संकोच न करें। राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसा भाषाई सद्भाव पूरे देश में दिखाई देना चाहिए। आज महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के इशारे पर हिंदी भाषी लोगों के साथ जैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वह उचित नहीं। ठाकरे बंधु इस तरह की भाषाई संकीर्णता और कट्टरपन से मराठी भाषियों का दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि हिंदी के माध्यम से उन्हें मान-सम्मान,

मेलबाक्स

पद-प्रतिष्ठा मिलने के साथ जो आर्थिक लाभ हो रहा है, वह एकमात्र मराठी भाषा से चिपके रहने से संभव नहीं। बहुल भाषा-भाषी भारत के किसी भी राज्य में भाषाई कट्टरपन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सर्वमान्य संपर्क भाषा हिंदी का विरोध न केवल दुर्भाग्यपूर्ण, अपितु भाषाई कट्टरपन का परिचायक भी है। केंद्र सरकार को समय रहते इस संबंध में कोई निर्णायक कदम उठाना चाहिए।

pandeyvp1960@gmail.com

पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध

जनता को तंग करने वाले फैसले- शीर्षक से छह जुलाई को प्रकाशित आलेख में संजय गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों पर पाबंदी को लेकर सही सवाल उठाए हैं। क्योंकि वर्तमान अत्याधुनिक तकनीक युग में कोई भी पुरानी मशीनरी फेंकने की जरूरत नहीं है और यही बात पुरानी कारों पर भी लागू होती है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध का फैसला जनता के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रदूषण कम करने की नीयत भले ही सही हो, लेकिन इसका तरीका असंतुलित और अव्यावहारिक है। हजारों वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां औने-पौने दामों में बेचनी पड़ रही हैं। 80 लाख रुपये की गाड़ी का पांच लाख रुपये में बिकना केवल आर्थिक नुकसान नहीं, देश की संपत्ति का भी दुरुपयोग है। प्रदूषण का मुख्य कारण केवल पुराने वाहन नहीं, बल्कि सड़क पर उड़ती धूल, अतिक्रमण के कारण लगने वाला ट्रैफिक जाम और इंजन की खराब दशा भी है। आज वाहन चालकों को जो प्रदूषण सर्टिफिकेट मिलते हैं, वे भी अधिकांशतः भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार हैं। न तो उनकी जांच सही होती है, न ही उनका पालन। होना यह चाहिए कि हर सर्विस सेंटर, वर्कशाप और मैकेनिक के पास उत्सर्जन जांचने और नियंत्रित करने के उपकरण हों। उन्हें यह अनिवार्य रूप से लागू भी करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों की मदद से पुराने वाहनों में उत्सर्जन सुधार की संभावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए कि वाहन निर्माता कंपनियां और सरकार मिलकर रेट्रोफिटिंग जैसी उपायों को बढ़ावा दें। साथ ही, पुराने वाहनों के पुर्जों का पुनः उपयोग और मरम्मत को बढ़ावा देकर देश के धन और जनता की जेब दोनों की रक्षा की जा सकती है। प्रदूषण रोकने के लिए समग्र और व्यावहारिक नीति समय की मांग है।

सुभाष बुद्धावन वाला, रतलाम, मध्य प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करता है भारत वर्तमान में, परंतु वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी एक प्रतिशत से भी कम है। अब इसमें वृद्धि की उम्मीद जगी है।

आजकल

वैश्विक हथियार बाजार में भारत की बढ़ेगी मांग

पश्चिमी देशों के एक महत्वपूर्ण सामरिक संगठन नाटो की बीते दिनों दहेग में एक बैठक संपन्न हुई है। यह बैठक इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि इसके 31 सदस्य देशों ने (केवल स्पेन को छोड़कर) वर्ष 2032 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी अपनी जीडीपी का पांच प्रतिशत रक्षा बजट पर खर्च करने के लिए सहमति दे दी है। हालांकि चीन और रूस दोनों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, परंतु रक्षा प्रणाली और हथियार बेचकर करोड़ों-अरब रुपये कमाने का भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है, जो उसे वर्ष 2030 तक विश्व के शीर्ष दस रक्षा निर्यातकों में पहुंचा सकता है

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

नाटो देशों का अपना रक्षा खर्च बढ़ाकर अपनी अपनी जीडीपी के पांच प्रतिशत पर लाने पर राजी होना, चीन और रूस दोनों के लिए चिंताजनक है। ट्रंप की चालाकियां, नीति-रणनीति और पैंतरे जो उसके साथ शामिल अधिकतर छोटे यूरोपीय देशों के लिए हों, हम पर खास असर न डालते हों तो इस बारे में हमारी खुशी क्या और चिंता क्या, लेकिन एक तो भू-राजनीतिक समीकरण इतने एक रेखीय नहीं होते, जितने अमूमन नजर आते हैं। उनमें कई परोक्ष अंतर्संबंध गुंफित होते हैं। तिस पर भारतीय विश्लेषकों का यह मानना है कि अमेरिकी प्रस्ताव जिसे धमकी कहना उचित होगा, स्वीकार लेने से नाटो के तमाम देशों का रक्षा बजट दोगुना-तिगुना होगा तो हमारे हथियार, सैन्य प्रणाली तथा उपकरण खूब बिकेंगे।

फ्रांस और अमेरिका के अलावा एशिया और अफ्रीका के साथ कई देश भारतीय हथियारों में रुचि ले रहे हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस खरीद रहा है तो वियतनाम नौसैनिक उपकरण, मारीशस, सेशेल्स, श्रीलंका वगैरह तटरक्षक पोत, लैटिन अमेरिका के कुछ देश भारतीय रडार और हल्के हथियारों में रुचि दिखा रहे हैं, तो हम नेपाल, म्यांमार, भूटान के अलावा इंडोनेशिया, ब्राजील और कुछ यूरोपीय देशों को भी हथियार बेचने जा रहे हैं। ऐसे में गैर नाटो देशों के अलावा कम से कम दो दर्जन नए नाटो ग्राहक मिलेंगे तो हम करोड़ों अरब कमाएंगे। इस तरह की प्रत्याशा से भरे समाचारों को प्रचुरता ने नीदरलैंड्स के द हेग में हुई बैठक के दौरान नाटो देशों के नए बजट की मंजूरी को अपने देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना के बराबर स्थापित कर दिया।

सवाल उठता है कि क्या विश्लेषकों का आकलन तर्कसंगत और सटीक है? अथवा अतिउत्साही और महज खुशफहमी भरा है? बेशक भारत अब बेहद उन्नत और सक्षम हथियार तथा सैन्य तकनीकी से संरचन उपकरणों-उपस्करों का निर्माण करता है, विश्व बाजार में उसकी साख भी बन रही है। वह हथियारों को बेचना भी अवश्य चाहेगा। पर क्या वाकई यह इतना आसान और बड़ा अवसर है, जिसका मुख्य दोहनकर्ता हमारा ही होगा? क्या यह मौका देश के हथियार बाजार को वैश्विक मंच दिलाएगा? क्या यह लाभ वाकई इतना बड़ा है जितना प्रचारित किया जा रहा है? नाटो के कोष में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी निभाने वाले अमेरिका के हाथ खींचने की धुंदुकी से उसके कुछ देश अपना रक्षा व्यय जीडीपी के पांच प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास करेंगे। पोलैंड अपनी जीडीपी का चार प्रतिशत से ज्यादा, एस्टोनिया और अमेरिका सवा तीन प्रतिशत से अधिक, लातविया और ग्रीस जो तीन प्रतिशत तक खर्ची हैं, वे ऐसा कर सकेंगे। फिलहाल इसमें ग्रीस के अलावा कोई दूसरा हमारा संभावित ग्राहक नहीं दिखता। ढाई प्रतिशत या उससे कम का आंकड़ा रखने वाले देशों के लिए यह काम आसान नहीं होगा, जिसमें फिनलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, डेनमार्क इत्यादि हैं और जो देश दो प्रतिशत या उससे भी नीचे यानी जो अपनी जीडीपी का एक प्रतिशत से जरा ही ज्यादा रक्षा मद में व्यय करते हैं, उनके लिए यह असंभव होगा।

भारत के लिए नई उम्मीद : नाटो के संगन और जीडीपी के तीन प्रतिशत से ज्यादा रक्षा व्यय करने वालों के पसंदीदा हथियार विक्रेताओं में अभी भारत शामिल नहीं। छोटे देश जिनका रक्षा बजट उनकी जीडीपी के तीन प्रतिशत तक पहुंच भी जाए तो यह राशि बेहद कम होगी। ऊपर से समूह के सदस्य देशों तथा अमेरिका और बाजार के दीगर बड़े खिलाड़ियों का भी दबाव होगा। नाटो देशों के हथियार और सैन्य सामग्री तथा उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता अभी भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ही हैं। बोइंग और लाकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी कंपनियों ने नाटो देशों का हथियार बाजार पहले से ही कब्जाया हुआ है, वे इस अवसर को भुनाने के लिए और आक्रामक प्रयास करेंगी। इनके अलावा, दक्षिण कोरिया इन देशों को उन्नत मिसाइल और नौसेना प्रणाली बेचने के करीब है, तो इजरायल और तुर्किये इन्हें सस्ते ड्रोंस, सइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस उपकरण तथा ब्राजील सस्ते में मिलिट्री विमान देने जा रहा है।

नाटो देश अब सस्ते और भरोसेमंद बैकलिफ हथियार स्रोत तलाश रहे हैं, सौ कुछ नाटो देशों से खरीदारी के प्रस्ताव मिलते भी हैं, तो उसका हमारे रक्षा व्यवसाय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि आज 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात करने के बावजूद भारत वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में एक प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी रखता है। विगत एक दशक में सरकार ने जो कोशिशें रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के नाम पर की हैं, उसके शानदार परिणाम अब दिखने लगे हैं और तय हो चुका है कि भारत रक्षा बाजार में भविष्य का बड़ा खिलाड़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस, अर्जुन टैंक, स्वदेशी रडार, आर्टिलरी गन, डीनीयर-228 विमान, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका राकेट जैसे तमाम निर्यात योग्य शानदार उत्पाद हैं। डेटा पैटर्न इंडिया, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलाजीज, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रानिक्स, भारत डायनेमिक्स, आइडियाकोज टेक्नोलाजी, एचएएल, टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनियां अपने उत्पादों और डिलीवरी के लिए वैश्विक स्तर पर जानी जा रही हैं। एमआरओ यानी मेंटीनेंस, रिपेयर, ओवरआल सेक्टर में भी हम बेहतर हैं। यदि हम अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता के धरातल पर रखें तो इस अवसर का लाभ हम टियर-2 सप्लायर के रूप में ले सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है वित्त वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात में 50 हजार करोड़ रुपये हासिल करने का उसे इसी तरह पूरा किया जा सकता है।

(ईआरसी)

वैश्विक परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन रही हैं जिसमें भारत के लिए हथियार बाजार में बड़े अवसर उपलब्ध हैं। फाइल

पाकिस्तान और तालिबान से रूस की बढ़ती निकटता

लोकमित्र गौतम

आपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ रूस का असमंजस रवैया और पिछले चार वर्षों में पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास से लेकर गैस पाइप लाइन बिछाने तक की योजना बनाना तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्रेमलिन में आमंत्रित करना, शायद रूस को भारत पर यह कूटनीतिक दबाव कुछ कम लग रहा था। इसलिए अब उसने तालिबान सरकार को मान्यता देकर रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक और खतरनाक गठजोड़ की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

गौरतलब है कि तालिबान का जहां एक धड़ा काफी पहले से हमारे साथ दोस्ताना संबंधों के लिए हाथ-पैर मार रहा था, वहीं इसका हक्कानी धड़ा भारत का विरोध और रूस, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के गठजोड़ की वकालत करता रहा है। हालांकि रूस खुले तौर पर तो ऐसा नहीं करेगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ बनाता दिखे, परंतु न दिखने से क्या होगा? अगर वह इन दोनों देशों के साथ मजबूत संबंधों की तिकड़ी बनाता है तो यह अपने आपमें भारत के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक मोर्चा होगा। यही नहीं, जिस तरह से रूस दुनिया का पहला देश बनते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है, उससे साफ है कि वह हर हाल में अफगानिस्तान को अपना मजबूत सहयोगी बनाना चाहता है। जिस तरह से अफगानिस्तान में एक बड़े तबके की हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है, उसके कारण रूस और अफगानिस्तान का यह गठजोड़ स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाएगा। इससे साफ है कि रूस का तालिबान को मान्यता देना भारत पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव है।

भारत हालांकि पिछले एक साल से तालिबान के साथ सकारात्मक संपर्क में है और पहलगाम की घटना के बाद अफगानिस्तान ने जिस तरह से इसका विरोध किया था, उससे साफ लग रहा था कि वह हमारे प्रति हमदर्दी रखता है। लेकिन यह भी साफ है कि भारत ने आज तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है और हाल फिलहाल में तालिबान सरकार को मान्यता देने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन अब रूस ने जिस तरह से तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है और अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान तक तेल और गैस आपूर्ति की पाइप लाइन बिछाने पर गंभीर चर्चा के मोड़ पर आ गया है, उससे साफ है कि हमें भी रूस, पाक और अफगान तिकड़ी को भारत के खिलाफ मजबूत कड़ी बनने से रोकने के लिए तालिबान के साथ दोस्ती की और मजबूत करना होगा, नहीं तो तालिबान अभी हमारे साथ अपने रिश्तों के भविष्य की उम्मीद में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ तटस्थ रवैया अपनाए हुए है, वह उससे पलटकर दुश्मन मोड में आ जाएगा और भारत के साथ विरोधी गठजोड़ की मुद्रा धारण कर लेगा।

लेकिन शेष दुनिया के लिए अभी तालिबान को मान्यता देना इतना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस ने रणनीतिक ढंग के चलते भले तालिबान को गले लगा लिया हो, लेकिन उसकी नैतिक साख मिट्टी में मिल गई है। पुतिन के अभी भी कई सरकारें और वहां के लोग पुराना कामरेड मानने की ही गलती करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने स्त्री विरोधी और धार्मिक रूप से उन्मादी तालिबान सरकार को मान्यता दी है, उससे सबकी आंखें खुल गई हैं कि पुतिन अपने फायदे के लिए किसी भी गधे-घोड़े को अपना बाप बनाने से परहेज नहीं करते। पुतिन की अब यह हरकत तालिबान के लालच को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी और जो तालिबान सरकार अभी तक भारत से परोक्ष रूप से रिश्ता बढ़ाने के लिए हमारे इंजीनियर मंडरी रही थी, वही अब ऐसा करने के लिए हम पर पाकिस्तान के नजदीक जाने का दबाव बना सकती है। क्योंकि रूस द्वारा मान्यता दिए जाने से उसका मनोबल कई गुना बढ़ गया है और रूस का यह दांव भारत पर भारी पड़ रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

संस्थान निर्माण की 'शिव-शक्ति'

कहते हैं कि संस्थाएं ईंटों, बीम और सीमाओं से बनती हैं। लेकिन हममें से जो लोग उनके निर्माण के दौर से गुजरते हैं, वे बेहतर जानते हैं कि संस्थाएं एकजुट इरादों, पसीने, धैर्य, संघर्ष, समझौते और लगाव से बनती हैं, क्योंकि आप अपने और दूसरों की भावनाओं एवं अहम से जूझ रहे होते हैं।

एक संस्था का निर्माण एक जीवन को जन्म देने जैसा है। 'शक्ति' का रूप जो अपने खून, उम्मीद और घाव को भर लेने से कहीं कम नहीं है। लेकिन ऐसे दिन अक्सर आते हैं जब व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराने लगती हैं, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि कहीं और कुछ आपकी गति से नहीं चल रहा है। 'एक ढीला पेंच' जिसे आप कसना भूल गए थे और उस पल में, भले ही यह आपकी गलती न हो, परिणाम आप तक आ पहुंचता है। वह आपकी लय को बाधित करता है, आपके प्रयास पर सवाल उठाता है। आप चीखना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं, 'गलती का यह हिस्सा मेरा नहीं था।' लेकिन अगर आप एक निर्माता हैं, तो आप सभी मतभेदों को साथ लेकर चलते हैं जो शायद किसी जहर के सामान लगते हैं। क्योंकि 'शिव' निर्माता हैं। वह रचना, व्यवस्था, देवों, असुरों के विवाद के आगे दीवार बन जाते हैं जो दूसरों को तूफान से बचाते हैं, भले ही तूफान उन्हें घायल कर दे।

संस्थानों के बनने के पश्चात एक दिन वर्षों बाद आप इमारत की बनावट पर अपनी उंगलियां फिराते हैं और एक अजीब सी खामोशी आपकी यादों में होती है। आप उस दिन जाने पाते हैं कि उन ईंटों के बीच सीमेंट ने आपके पसीने को थाम रखा था। वह दीवारें आपकी लड़ाइयों, विश्वास और रातों की नींद की कहानी बयां करती हैं। वह 'रण' समुद्र का मंथन था जिसका विष प्याला कभी आपने पिया था। और फिर एक दुर्लभ शांत क्षण में आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपके शिव, शक्ति के मेल ने दुनिया को कुछ वास्तविक दिया जो उन लोगों के सपनों का मार्गदर्शन करेगा जो कभी आपके 'नाम' को नहीं जान पाएंगे, परंतु फिर भी आपके द्वारा चुपचाप आपके बनाए गए रास्तों पर चलेंगे।

(डा. गुंजन सिंह राजपूत की फेसबुक प्राल से संपादित अंश, साभार)

X पोस्ट

हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भाषा न आए तो इंसान का अपमान भी गलत है।

सुचरिता कुकरेती @sucherita_k

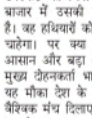

मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृति के बाद भी डेढ़ साल चंद्रचूड़ महीनों तक उस आवास में रह रहे हैं, जो उन्हें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मिला था। अंततः सुप्रीम कोर्ट को यह आवास तत्काल खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को लिखना पड़ा। क्या इस प्रकरण को लेकर न्याय, नैतिकता, विधि के शासन और अधिकारों आदि की चर्चा सुनने को मिलेगी?

मुदित गुप्ता @mudit_gupta25

रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को पीछे छोड़कर भारतीय टीम में एक नया बल्लेबाजी क्रम उभरा है। टेस्ट में हम गेंदबाजी या तीन धचन को लेकर यहां जो कहते रहें, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस नए बल्लेबाजी क्रम पर दांव लगाने का धचनकर्ताओं-टीम प्रबंधन का फैसला बहुत बहादुरी भरा रहा। बल्लेबाजी ने इस भरोसा में अभी तक किसी भी तरह से निराशा नहीं किया।

जोय भट्टाचार्य @joybhattacharj

उत्तर प्रदेश डायरी

सत्ता के दो ध्रुवों के बीच गढ़ में गृह प्रवेश!

भारतीय वसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कवायद और कयास के अनेक दौर चल रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी यह उपक्रम जारी है। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के नैरेटिव की काट प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चयन में ढूंढी जा रही होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ठोर राजनीतिक-सामाजिक निहितार्थ से आजमगढ़ में अपना गृह प्रवेश किया है। पूर्वांचल की राजनीति में अपनी पैठ और गहरी करने के लिए मैनपुरी, सैफई, लखनऊ के साथ-साथ आजमगढ़ में नए भवन में प्रवेश को लेकर अखिलेश का उत्साह उनके बयानों में उमग रहा है।

आजमगढ़ के उत्तर में गोरखपुर है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और उसके दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। दलगत शक्ति के इन दो ध्रुवों के बीच अपने स्पेस को बचाए रखने की जुगत अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगी। दोनों ध्रुव के मध्य आजमगढ़ घोषित तौर पर सपा का गढ़ है। इस समय आजमगढ़ की सभी दस सीटों पर सपा के विधायक हैं और दोनों लोकसभा सीटें भी उसके ही खाते में दर्ज हैं।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 62 से 33 सीटों के अवरोह को रोकने या आरोह की ओर बढ़ने के लिए सपा के पीडीए (पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यक) बनाम भाजपा के पीडी (पिछड़ा-दलित) नैरेटिव के काल-कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। सामने पंचायत चुनाव और उसकी पीठ पर सवार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों से लेकर विधान पश्चिद सदस्यों की सूची रोज उलटी-पलटी जाती रहती है, पर यह भी सच है कि इस पार्टी में हमेशा औचक और अपूर्वानुमानित नाम के सिर सेहरा बंध जाता है। घोषणा से पूर्व कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए कौन अंतिम नाम है। पिछड़ी और दलित जातियों के कई उपनाम चर्चा के लिए तलाश लिए गए हैं। जाट भूपेन्द्र सिंह चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनसे पूर्व भी औबीसी अध्यक्ष रह चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में और स्वतंत्रदेव सिंह 2022 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सामने पंचायत चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी सोशल इंजीनियरिंग में लगी हैं।

आजमगढ़ के अनवरगंज में जिस आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय का अखिलेश ने उद्घाटन किया है, उस भवन का नाम ही पीडीए भवन रखा गया है। अखिलेश ने कहा है कि सैफई के बाद यह उनका दूसरा स्थायी पता होगा और यह भवन ही पूर्वांचल में पार्टी का मुख्यालय भी होगा। पीडीए भवन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा की संरचनात्मक नींव है। 11 किसानों को सवा छह करोड़ रुपये देकर यह जमीन वर्ष 2021 में खरीदी गई थी। पूर्वांचल के हिस्से में 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वांचल की डेमोग्राफी में सपा का पीडीए फार्मूला मुफीद बैठता है। यादव, कुर्मी, राजभर, कुशवाहा के साथ ही अल्पसंख्यकों का अच्छा दखल है। पार्टी के अब तक के लोकसभा चुनाव परिणाम में सबसे श्रेष्ठ परिणाम 2024 का लोकसभा चुनाव ही रहा है। 37 सीटें सपा के खाते में आई हैं। कभी मुलायम सिंह ने कहा था कि अगर मैनपुरी उनका दिल है तो आजमगढ़ उनकी धड़कन। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में दस सीट, वर्ष 2017 के चुनाव में नौ सीट और 2022 के चुनाव में पार्टी को सभी दस सीटों पर यहां विजय हासिल हुई है। हालांकि, मुलायम परिवार के इस सुरक्षित तौर में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उम्मीदवार बनाकर भाजपा की सेंध भी लगी थी। अखिलेश का घर सपा के घेरे की कितनी मजबूती देता है इसकी परख शेष है।

आजमगढ़ में नवनिर्मित भवन जहां अखिलेश यादव ने हाल ही में किया है गृह प्रवेश। फाइल

आम महोत्सव और राजनीतिक रस का मीठा-कड़वा स्वाद : आम के इस मौसम में राजनीति का रस शास्त्र नए-नए स्वादों का प्रकटीकरण कर रहा है। आयुर्वेद में रस शस्त्र का मुख्य उद्देश्य औषधीय गुणों वाले पदार्थों का उपयोग करके विभिन्न रोगों का इलाज करना है। इधर, आम महोत्सव 2025 के ठीक एक दिन पहले राजधानी में राजनीतिक रस शस्त्र का कड़वा स्वाद भी घुलता रहा। प्रसेन सौनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस का है। दिवस की पूर्व संध्या पर अपना दल का एक गुट अपने बागी होने का भाव पैदा करता है। परिणाम सामने था। स्वाभिमान दिवस का समस्त आयोजन अब नाट्य शास्त्र के रौद्र रस का रूप ले लेता है। बागियों के अलग से अपना मोर्चा बनाने से खफा दल के प्रमुख आशीष पटेल ने संकेतों में भाजपा को ही अपने निशाने पर रखा। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि आशीष मंत्री पद का मोह त्याग देंगे। यह सब आकस्मिक नहीं है। अपना दल की सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल ने जब प्राथमिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और धरना दिया था, तब भी आशीष 'अनुग्रय समर्थन' या 'खामोशी' पर सवाल खड़े कर रहे थे। फिलहाल, सवाल ही सवाल हैं और जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से दोनों को राजनीतिक मजबूती मिलेगी?

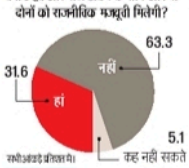

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नई पार्टी बनाकर एलन मस्क अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं?

परिणाम जागरण हंटरमेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मिल ने जीता दिल पुनः डेढ़ सेंचुरी मार,
कप्तानी कार्ड रहे बार-बार उपहार।
बार-बार उपहार ही रही छाती चौड़ी,
जाड़ेला के साथ उम्र रही बढ़िया जोड़ी।
दिखलाया है खेल वही जो मांगा दिलने,
चौके-छक्के मार किया खुश शुभम्म मिलने!

- ओमप्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

मानसूनी मौसम में पक्ष-विपक्ष

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

प्रदेश के नए मुख्य सचिव की तलाश की प्रक्रिया को अगले तीन महीनों के लिए टालते हुए सत्ता पक्ष मानसून सत्र की तैयारी में जुट गया है। तय है कि आनेवाला सप्ताह राजनीतिक गरमागरमी का रहेगा। मानसून के साथ बयानों की भी झमाझम बारिश तय है। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और महासचिव केसी वेणुगोपाल होंगे। भाजपा अपने सांसदों और विधायकों की मुद्दे उठाने और उत्तर देने का प्रशिक्षण देगी तो कांग्रेस किसान, जवान और संविधान के मुद्दे के साथ मैदान में होगी।

प्रदेश के 25 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून को अमिताभ जैन बिदाई से पूर्व राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात भी कर चुके थे। आइएएस अधिकारी सुब्रत साहू और मनेज पिंगुआ के साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अमित अग्रवाल में से किसी एक की चुना जाने था। नए मुख्य सचिव के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले केंद्र से संदेश आ गया और अचानक समीकरण बदल गया। यह संयोग ही हो सकता है कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से अशोक जुनेजा की फरवरी माह में सेवानिवृत्ति के बाद से अरुणदेव गौतम कार्यकारी डीजीपी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह सब विपक्ष के पास प्रदेश सरकार में अनिर्णय की स्थिति पर प्रश्न खड़ा करने का मुद्दा भी बन गया है।

यही कारण है कि गुटों में बंटी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पहल की है और किसान, जवान और संविधान सभा के माध्यम से प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की रणनीति बनाई है। निशाने पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार होगी जिस पर संविधान और संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रहार करने का कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता संकेत दे चुके हैं कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के साथ ही आदिवासियों और बीचौलों का मुद्दा भी उठेगा। किसानों के समर्थन में खाद-बीज का मामला भी चर्चा में रहेगा। इसके साथ ही बस्तर में माओवादियों से संघर्ष और औद्योगिक प्रगति के प्रयासों में भी कांग्रेस प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभाने के प्रयास में दिखेगी। यद्यपि यह सर्वविदित है प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह स्तर पर है। यह और स्पष्ट हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में भाजपा सरकार की विफलताओं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत के हमलावर नहीं होने का आरोप लगाया। जबाब में डा. महंत ने घोषणा कर दी कि मानसून सत्र में लाप्री लेकर विधानसभा जाएंगे। उनकी हंसी में उपहास तो था ही प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों में एक के बाद एक नेताओं और अधिकारियों के जेल जाने के प्रति उपेक्षा भी थी। इस बात पर पार्टी के अंदर ही संदेह है कि कांग्रेस की सभा प्रदेश के नेताओं में किसी प्रकार तालमेल कायम करने में सफल रहेगी।

इसी दौरान भाजपा के विधायक अगले तीन दिनों तक सरगुजा के मैनपाट में होंगे। रोपवाइर जलाशय के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीन दिवसीय सांसद-विधायक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करेंगे तो गृह मंत्री अमित शह देश के सम्मुख चुनौतियों के समाधान में भाजपा की भूमिका बताएंगे। जनप्रतिनिधियों को विकसित छत्तीसगढ़ में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भी मंथन होगा। इन सबके बीच शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक मजबूत संदेश देने में सफल रहे हैं। लगभग सवेंद चार सौ शिक्षकविहीन और पांच हजार एक शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती ने प्रदेश में हलचल की स्थिति उत्पन्न कर दी है। 13 हजार से अधिक शिक्षकों के तबादले से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। इस तरह अन्य विभागों के मंत्रियों के समक्ष भी लंबे समय से एक ही स्थानों पर जमे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को सही स्थानों पर नियुक्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इनसे जुड़े मामले भी चुनावी सभा में उभरेंगे, परंतु कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि सोमवार को भारी बारिश के बीच उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए कितने कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच पाते हैं।

प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए विष्णु देव साय। (बाएं)। डीपीआर

****

मतदाता पहचान

जटिल कार्रवाई

मतदाता पहचान एक जटिल कार्रवाई है। निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान अभियान ने राजनीतिक पार्टियों को असहज तथा मतदाताओं को भयभीत किया है। बिहार में चुनाव कुछ ही महीने बाद हैं और राज्य में एक राजनीतिक तूफान सिर उठा रहा है। यह कोई राजनीतिक अभियान न होकर भारतीय निर्वाचन आयोग-इंसीआई का मतदाता पहचान अभियान है। इसने करोड़ों मतदाताओं को डरा दिया है कि इंसीआई के निर्णय से उनको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। यह मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के अंतर्गत वर्तमान एवं नए मतदाताओं से नए दस्तावेज मांग रहा है। जब करोड़ों लोग आवास, जाति या अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब विपक्षी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव एलायंस'-इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। उसने इस कदम को जानबूझ कर हाशियाकृत समुदायों और युवा मतदाताओं का मताधिकार छीनने का प्रयास बताया है जो परंपरागत रूप से उसका समर्थन आधार रहा है। इंसीआई के नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है अथवा वह इस सूची में दर्ज मतदाता का वारिस नहीं है तो उसे अब अपनी नागरिकता और पहचान सिद्ध करने के लिए अधिकारिक रूप से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना होगा। इनमें जाति प्रमाणपत्र, स्थाई आवास प्रमाणपत्र व अन्य शामिल हैं। इस उद्देश्य से आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले आधार कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड या यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र वैध नहीं हैं। इस त्वरित निर्देश के क्रियान्यन के लिए केवल 25 दिन का समय दिया गया है जिससे राज्य भर में घबराहट और भ्रम का माहौल पैदा हो गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता आवश्यक दस्तावेज जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, पर आदेश की जटिलता के कारण संभवतः बड़ी संख्या में मतदाता इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव में सहभागिता न कर पाएं। खासकर महिलाओं, युवा मतदाताओं तथा रोज कमाने-खाने वालों में से अनेक के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं और समय, सूचना एवं संसाधनों के अभाव में वे शायद इनको न प्राप्त कर सकें। हाशियाकृत समुदायों में मतदाता सूची से बाहर होने की चिन्ता निराधार नहीं है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया न केवल जटिल है, बल्कि यह खासकर राज्य से बाहर काम करने वालों या नई आवश्यकताओं से अनजान लोगों के लिए अपरिचित एवं चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ ही जुलाई के अंत की समयसीमा को देखते हुए 7.8 करोड़ मतदाताओं की पुष्टि लगभग असंभव है। 'इंडिया' समूह तथा खासकर राजद व कांग्रेस ने इंसीआई पर आरोप लगाया है कि वह दबाव में कथित 'चयनित मतदाता सफाई' के लिए काम कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों, जनता तथा नौकरशाहों द्वारा व्यक्त की जा रही चिन्ता ने इस कार्रवाई की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंसीआई को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव गरीबों, निरक्षरों, नौजवानों तथा प्रवासी कामगारों पर पड़ेगा। इसके साथ ही यह बात समझ से परे हैं कि अचानक सरकार द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्रों का प्रयोग वैध क्यों नहीं रह गया है।

निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाए रखने तथा साफ करने और मतदाताओं की पुष्टि का वैध कदम है। हालांकि, अब तक केवल तीन प्रतिशत ने ही ईसीआई के पोर्टल पर अपने दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए हैं जो लाजिस्टिक चुनौती को रेखांकित करता है। ईसीआई ने 2003 में किए ऐसे संशोधनों का उदाहरण देते हुए कहा है कि वर्तमान समय में जारी दस्तावेजीकरण प्रयास पहचान और आवास निर्धारित करने का मानक है। लेकिन इसके समय, तात्कालिकता तथा तीव्रता पर कुछ सवाल उठते हैं। यदि यह कार्रवाई इतनी जरूरी थी तो इसे चुनाव के कुछ ही महीने पहले के बजाय काफी पहले से किया जा सकता था। अभी यह निश्चित नहीं है कि ईसीआई समयसीमा या मानकों की ढिलाई पर पुनर्विचार करेगा या नहीं, पर बिहार चुनाव का रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण होना निश्चित है।

भारतीय मुसलमानों में कट्टरपंथ

भारत में दो प्रभावशाली इस्लामी आंदोलन-जमाते इस्लामी और तबलीगी जमात युवा भारतीय मुसलमानों का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदलने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इससे उनमें कट्टरपंथ बढ़ रहा है।

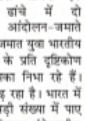

शुजात अली कादरी
(लेखक, एक छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं)

भारत के जटिल धार्मिक एवं सामाजिक ढांचे में दो प्रभावशाली इस्लामी आंदोलन-जमाते इस्लामी और तबलीगी जमात युवा भारतीय मुसलमानों का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदलने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इससे उनमें कट्टरपंथ बढ़ रहा है। भारत में अनेक धर्मों के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जिससे एक जटिल व संवेदनशील सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य बनता है। इस परिदृश्य में मुस्लिम संगठन मुस्लिम जनता की पहचान, विश्वास और सामुदायि व्यवहार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि, देश के विभिन्न भागों में अनेक मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं, पर इन संगठनों में जमाते इस्लामी व तबलीगी जमात ने ऐतिहासिक रूप से स्वयं को इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के रूप में पेश किया है। हालांकि, सार्वजनिक रूप से उन्होंने हिंसा को खारिज कर दिया है, पर इस बारे में चिन्ता बनी हुई है। मुख्य सवाल यह है कि क्या उनकी विचारधारा, वैचारिक ढांचा तथा उनके प्रभावक्षेत्र में आने वाले नेटवर्क भारत में मुस्लिम नौजवानों के कुछ तबकों का उग्रवादीकरण कर रहे हैं। इस बारे में अनेक राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषकों ने समय-समय पर सवाल उठाए हैं। इस लेख में हम इन व्यवस्थाओं, विमर्शों और पैटर्नों को उजागर और विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से ये समूह काम करते हैं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि उनके सिद्धान्तों का झुकाव किस प्रकार विशिष्टतावाद, अलगाववाद और यहां तक कि अतिवाद की ओर है।

जमाते इस्लामी और तबलीगी जमात का विकास पिछले सालों में धार्मिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान से राजनीतिक एजेंडे की ओर हुआ है। इन संगठनों के अपने प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनीति एजेंडे हैं जिनसे वे देश की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में अबुल आला मौदूदी ने की थी और यह केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं है। इसका आधार इस्लाम की राजनीतिक व्याख्या है और यह शरीया पर आधारित इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहता है। हालांकि, जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है, पर यह बाकी भारत में कार्यरत है। यह विभिन्न नामों और मोर्चों के माध्यम से छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों के रूप में सक्रिय है। दूसरी ओर तबलीगी जमात स्वयं को अराजनीतिक बताता है और अंतर्मुखी संगठन के रूप में मुस्लिम जनता की व्यक्तिगत पवित्रता तथा इस्लामी धर्म प्रचार-'दावा' पर जोर देता है। यह गैर-मुस्लिमों के बजाय मुस्लिमों पर ही ध्यान देता है और उनको शुद्धीकरण या प्रकारान्तर से कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहता है।

लेकिन इसके द्वारा प्रचारित इस्लाम कठोर, देवबंदी विचारों के आधार पर तथा आधुनिकता-विरोधी है। वह बहुलतावाद को हतोत्साहित करने के साथ ही ऐसी विश्व दृष्टिकोण पर जोर देता है जहां धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान पर वरीयता मिलती है। तबलीगी जमात पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह ऐसा माहौल बनाता है जिसमें नौजवान मुख्यधारा समाज से अलग हट कर केवल कट्टर मुसलमान बन जाते हैं। हालांकि, इन दोनों समूहों की कार्यप्रणाली में अंतर है, पर जहां जमाते इस्लामी राजनीति पर जोर देता है और तबलीगी जमात आध्यात्मिकता को केन्द्र में रखती है, लेकिन ये दोनों ही एक द्विध्रुवी सोच को प्रोत्साहित करते हैं जिसमें 'हम बनाम वे' विमर्श अलगाव को बढ़ावा देता है। जमाते इस्लामी का सर्वाधिक दृश्यमान चेहरा उसकी छात्र शाखा है। स्वयं को शिक्षा और सामाजिक न्याय के मंच की तरह पेश करने वाली इसकी छात्र शाखा अक्सर जमात की वैचारिक समझदारी प्रकट करती है। यह सेक्युलरवाद का विरोध करने के साथ ही इस्लामी शासन को गौरवान्वित करती है तथा सामुदायिक पहचान को मजबूत करती है। केरल, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के परिसरों में जमाते इस्लामी की छात्र शाखा ने ऐसा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता समूह तैयार किया है जो आधुनिक राजनीति और पश्चिमी उदारतावाद को इस्लाम-विरोधी के रूप में देखते हैं।

ये युवा कार्यकर्ता अक्सर संवेदनशील तरीके से 'बौद्धिक इस्लाम' की आड़ में लोकतंत्र-विरोधी विचारों को पेश करते हैं। हालांकि, वर्तमान समय में तबलीगी जमात ने लो-प्रोफाइल अपना रखी है, पर चालीस दिन की मिशनरी यात्राओं-'चिल्ला' के माध्यम से उसने युवा समर्थकों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया है। इन युवाओं को नियमित शिक्षा या रोजगार छोड़ने, स्वयं को 'गैर-इस्लामी परिवेशों' से अलग करने तथा अपना जीवन 'उम्मा' को शुद्ध करने के काम में लगाने को प्रेरित किया जाता है। दोनों समूह अपनी घोषित रणनीति में अहिंसक हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे गैर-उग्रवादी हैं। इस उग्रवादीकरण प्रक्रिया का संबंध हमेशा हिंसा से नहीं होता है, पर इसका अर्थ निश्चित रूप से ऐसी सोच बनाना है जो अलगाववाद को सामान्य बनाती है, संवैधानिक मूल्यों को अस्वीकार करती है तथा 'दूसरों' पर अविश्वास करती है। इन समूहों में शामिल अनेक युवा मुस्लिम लोकतांत्रिक सहभागिता, सेक्युलर शिक्षा, अन्य धर्मों के साथ सह-अस्तित्व तथा भारत के बहुलतावादी समाज में समावेशन पर सवाल उठाने लगे हैं। इस प्रकार ऐसा 'स्पेस' बनता है जहां ज्यादा उग्रवादी तत्वों को आसानी से भर्ती किया जा सकता है। वास्तव में अतीत की अनेक खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आतंकी घटनाओं में शामिल या बाद में आईएसआईएस में शामिल होने वालों की पृष्ठभूमि इन वैचारिक समूहों से जुड़ाव की रही है। वास्तव में जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर ऐसा वैचारिक प्रचार करने का आरोप है जो बाद में उग्रवाद को जन्म देता है। हालांकि, यह समूह आतंकी संगठनों से अपने जुड़ाव से इनकार करता है, पर इसका साहित्य अक्सर भारतीय राज्य को उत्पीड़क के रूप में पेश करता है। आधुनिक उग्रवादीकरण के लिए किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस एक स्मार्ट फोन, इंटरनेट कनेक्शन और अनियंत्रित विषयवस्तु की जरूरत होती है। जमाते इस्लामी और तबलीगी जमात नेटवर्क इनका उपयोग करते हैं।

मौदूदी या जाकिर नायक की विषयवस्तु को आगे बढ़ाने वाले वाट्सएप समूह, भारतीय मुख्यधारा में समावेशन को हतोत्साहित करने के यूट्यूब पर उपदेश तथा भारतीय राज्य के खिलाफ षड़यंत्र के संदेशों का साझा करने वाले टेलीग्राम चैनल इनमें शामिल हैं। यह मीडिया अब नरम उग्रवादीकरण की उपजाऊ जमीन बन गया है। इन दोनों आंदोलनों के बीच निकट संबंध हैं। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान-आधारित नेटवर्कों से वैचारिक समर्थन मिलता है और तबलीगी जमात बांग्लादेश, मलेशिया और ब्रिटेन जैसे देशों में अपने समकक्षों से जुड़ा है। हालांकि, इन देशों में अतिवाद को प्रोत्साहित करने केअरोप में इन संगठनो पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इन समूहों पर केवल प्रतिबंध लगाना ही काफी नहीं है। इस मामले में जीवन्त सिविल सोसाइटी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसमें समावेशी सूफी व अंतर-धार्मिक संवाद जैसी इस्लामी स्कालरशिप को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक व अकादमिक प्लेटफार्मों के माध्यम से मुस्लिम नौजवानों की मेंटरशिप, समुदायों पर निगाना लगाए बिना डिजिटल प्रचार पर नजर रखना तथा राज्य द्वारा मध्यमार्गी मुस्लिम स्वरों को खासकर स्थानीय व विश्वविद्यालयी स्तर पर बढ़ावा देना शामिल है।

सरकारी एजेंसियों को वैध धार्मिक अभिव्यक्तियों तथा वैचारिक शिक्षण के बीच अंतर करना चाहिए। मुस्लिम समुदायों को भी अपने भीतर झांक कर उन चुनौतियों को वरीयता देनी चाहिए जो शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके सामने हैं। वैचारिक साफ्ट पावर के माध्यम से भारतीय मुसलमानों का मौन उग्रवादीकरण सेक्युलरवाद और राष्ट्रीय एकीकरण के विचारों के समक्ष गंभीर चुनौती है, चाहे वह जमाते इस्लामी के राजनीतिक इस्लाम के माध्यम से हो या तबलीगी जमात की कट्टर शुद्धतावाद के माध्यम से। समय आ गया है कि न केवल राज्य, बल्कि सिविल सोसाइटी तथा स्वयं मुस्लिम समाज के माध्यम से इनके खिलाफ आक्रामक व समावेशी हस्तक्षेप किया जाए। उग्रवादीकरण के खिलाफ लड़ाई केवल अदालतों या पुलिस थानों में ही नहीं जीती जा सकती है। इसे लोगों के दिमागों, कक्षाओं तथा डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी सुधार, तर्क तथ जिम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से लड़ना होगा।

उपभोक्तावाद और नगरीय जीवन शैली

> आज उपभोक्ता केवल खरीदारी करने के लिए मॉल में नहीं जा रहे हैं, वे खोज करने, आराम करने और जुड़ने के लिए आ रहे हैं।

जतिन गोयल
(लेखक, स्तम्भकार हैं)

लेन देन संबंधी उपभोक्तावाद की पारंपरिक धारणा अब इमर्सिव और अवकाश-आधारित जुड़ाव द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही है। रिटेल लेवल-अप - द एंटरटेनमेंट एडिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार, औसतन, 65 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने केवल मनोरंजन के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना या उन्हें भोजन और पेय पदार्थों के साथ जोड़ना पसंद किया। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आज उपभोक्ता केवल खरीदारी करने के लिए मॉल में नहीं जा रहे हैं, वे खोज करने, आराम करने और जुड़ने के लिए आ रहे हैं। महामारी के बाद का युग एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन, विकसित जीवन शैली और विशिष्ट अनुभवों की इच्छा लेकर आया है। उपभोक्ता अब ऐसे खुदरा गंतव्यों की तलाश करते हैं जो सामाजिक मिलन स्थल के रूप में काम करते हों।

इससे खुदरा विकास की बढ़ती मांग हुई है जो भोजन, खरीदारी, दैनिक जरूरतों और मनोरंजन को व्यापक पेशकश प्रदान करते हैं - सभी एक ही स्थान पर। विशेष रूप से, पारिवारिक मनोरंजन केंद्र भीड़ को खींचने और भारी आकर्षण लाने की अपनी क्षमता के साथ अन्य क्षेत्रों से आगे निकल रहे हैं। जिन्हें कभी मॉल के एक कोने में एक परिचीय ऐड-ऑन माना जाता था, ये केंद्र अब प्राथमिक लंगर के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं। इन केंद्रों में, इनडोर मनोरंजन केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं और खुदरा क्षेत्र में मुख्य अपेक्षा के रूप में उभर रहे हैं। जेएलएल के अनुसार, भारत में इनडोर मनोरंजन केंद्र लोकप्रिय हो रहे हैं, वर्तमान में 83 शहरों में 500 से अधिक ऐसी सुविधाएं संचालित हैं, जो 66 लाख वर्ग फुट खुदरा स्थान को कवर करती हैं। इन केंद्रों में मनोरंजन और अवकाश के अनुभव प्रदान करने के लिए खेल और

आकर्षण का संयोजन है। देश में संचालित ड्रम में से लगभग आधे गेमिंग जोन प्रारूप में हैं, इसके बाद ट्रैम्पोलिन पार्क और उभरते मनोरंजन प्रारूप हैं। रिपोर्ट आगे दिखाती है कि 2028 तक इनडोर मनोरंजन केंद्र का स्टॉक 11 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने की उम्मीद है। बड़े खुदरा विकास और मॉल में अधिक विशाल और अभिनव केंद्रों को समायोजित करने की उम्मीद है। इसके अलावा जैसे-जैसे ये केंद्र बड़े पैमाने पर और परिष्कृत होते जा रहे हैं, मॉल जोनिंग को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है।

एफएंडसी को अब जानबूझकर उच्च-यातायात क्षेत्रों, जैसे कि फूड कोर्ट, कैफे और बच्चों के स्टोर के बगल में रखा गया है, जिससे मनोरंजन और भोग-विलास का एक निर्बाध चक्र बन रहा है। इसके अलावा, उपभोक्ता वरीयताओं के तेज गति से विकसित होने के साथ, चपलता एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बन गई है। मॉल के ब्लूप्रिंट को नई वास्तविकता को समायोजित करने के लिए फाड़ा और फिर से तैयार किया जा रहा है - जहाँ अनुभव हर चीज पर हावी है। बड़े फ्लोर प्लेट्स को बड़े पैमाने पर स्वश्रेष्ठ के लिए बनाया जा रहा है, जबकि पूरे स्तरों को समर्पित मनोरंजन डेक में बदला जा रहा है, जिसमें इमर्सिव जोन, थीम वाले आकर्षण और इंटरैक्टिव तकनीक शामिल हैं। इस विकास का नेतृत्व डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है जो समझते हैं कि खुदरा व्यापार का भविष्य ऑकेस्ट्रेटेड, उच्च-प्रभाव वाले अनुभवों में निहित है।

वैश्विक स्तर पर भी, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर बाजार का 2024 में 15 बिलियन से बढ़कर 2034 तक 27 बिलियन होने का अनुमान है, जो 6.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। एक्सेक्विटएड कंसल्टेंसी की नई जारी रिपोर्ट में स्वश्रेष्ठ को व्यापक अवकाश और आकर्षण उद्योग के भीतर एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्थान दिया गया है, जिसमें वैश्विक क्षेत्रों में इमर्सिव, सामाजिक रूप से समावेशी मनोरंजन विकल्पों की बढ़ती मांग से विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

बाजार का यह विकास उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न आयु समूहों में साझा अनुभवों पर अधिक जोर दिया गया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां परिवार, किशोर और वयस्क समूह सक्रिय रूप से उच्च गुणवत्ता वाले मनोरंजक स्थलों की तलाश कर रहे हैं। इसमें एडुटेनमेंट सेगमेंट और ट्रैम्पोलिन पार्क और बॉलिंग एली की एड्रेनालाईन-फ्यूल वाली अपील को जोड़ दें, और डेवलपर्स लगातार मॉल और रिटेल स्पेस को नया रूप दे रहे हैं।

इसलिए, एफएंडसी का भविष्य पहले से ही बदल रहा है - शुद्ध खेल से उद्देश्यपूर्ण खेल की ओर। जैसे-जैसे उपभोक्ता अपेक्षाएँ इमर्सिव, इंटरैक्टिव और भावनात्मक रूप से पुरस्कृत अनुभवों की ओर विकसित होती हैं, केंद्रों ने खुद को भीड़ खींचने वाले और राजस्व बढ़ाने वाले दोनों के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।

आप की बात

दीदी की दूकान

देश में महिलाओं का स्वरोजगार की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में शुरू हुइ-दीदी की दुकान, पहल इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है। यह पहल ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की महिलाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम बन रही है। दीदी की दुकानों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ महिलाओं की खास जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। खास बात यह है कि ये दुकानें न केवल उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सस्ते उत्पाद उपलब्ध करवा रही हैं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही हैं। आज जब बाजार में कुछ बड़े व्यवसायियों और ऑनलाइन कंपनियों द्वारा घटिया क्वालिटी के महंगे उत्पाद बेचे जा रहे हैं तब लोकल महिला उद्यमियों द्वारा संचालित ये दुकानें भरोसे का प्रतीक बन रही हैं। यदि महिलाएं संगठित होकर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को वाजिब दाम पर उपलब्ध कराएंए तो यह न केवल उनकी आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी। महिला उद्यमियों की सफलता से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी। इसके लिए आसान कर्ज, प्रशिक्षण व विपणन सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए।

- **विभूति बुपक्या**, खाचरौद

अंतरराष्ट्रीय क्षमा दिवस

हर वर्ष 7 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है जो दुनिया भर में क्षमा, सहिष्णुता और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह ऐसा दिन है जब हम अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं तथा अपने व्यवहार, विचार और कार्यों पर आत्ममंथन कर उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिन्हें हमने जाने-अनजाने में दुख पहुंचाया हो। हालांकि इस दिवस की ऐतिहासिक उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, परन्तु क्षमा की भावना हर संस्कृति और धर्म में प्रमुख रूप से उपस्थित रही है। विशेषतः भारत की परंपरा में क्षमा को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। जैन धर्म में क्षमवाणी या क्षमापना दिवस बहुत ही पवित्र दिन होता है जब अनुयायी एक-दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म कहकर सभी प्रकार की भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक मानवीय मूल्य है जो रिश्तों को मजबूत करने और अहंकार को त्यागने की प्रेरणा देता है। आज जब पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में युद्ध, हिंसा, घृणा और द्वेष की आग में जल रही है तब क्षमा जैसी भावना की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। यदि सभी नेता क्षमा का मार्ग अपनाएं तो हजारों निर्दोषों की जान बचाई जा सकती है।

- **सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के समय आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 7.5 प्रतिशत संविधान सम्मत आरक्षण प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक यह नियम लागू होगा। निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि जुलाई, 1997 में दिए एक आदेश को लगभग 29 वर्ष बाद अब जाकर लागू किया गया है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इस प्रावधान के तहत अब अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा जो कि संविधान की मूल भावना है। इस संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले जस्टिस गवई दूसरे दलित व घोषित बौद्ध न्यायाधीश हैं। उनके इस निर्णय से इन समुदायों का सम्मान भी बढ़ा है। उम्मीद है कि जस्टिस गवई अपने संक्षिप्त कार्यकाल में ऐसे अनेक सराहनीय निर्णयों के भागीदार बनेंगे।

-**वीरेन्द्र कुमार जाटव**, दिल्ली

पर्यटन का विरोध

बार्सिलोना में पर्यटन क्षेत्र और पर्यटकों को ब्रेक लगाने के लिए एक अनोखा आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को पर्यटन स्थलों से दूर करने के उद्देश्य से एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में कई स्थानीय निवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। तेजी से बढ़ते पर्यटन, पर्यटकों के अनुशासनहीन व्यवहार और इससे होने वाली महंगाई व अशांति के कारण स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो इस भीड़भाड़ और अव्यवस्था से तंग आकर अपने घर छोड़ दिए और शांत जगहों पर जाकर बस गए। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नारा लगाया बस बहुत हो गया, अब रोको यह पर्यटन और पर्यटक। एक महिला प्रदर्शनकारी ने प्लास्टिक की बॉटल गन से पर्यटकों पर पानी की बौछार कर दी। यही घटना एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बन गई। अब बॉटल गन यूरोप भर में पर्यटन के विरोध का प्रतीक बन गई है। नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, फ्रांस व पुर्तगाल जैसे देशों में लोगों ने इसी तरह पर्यटकों का विरोध शुरू किया है। बॉटर गन आंदोलन को गंभीरता से लिया जा रहा है।

- **दत्तप्रसाद शिरोडकर**, मुंबई

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।